● वर्ष : 17 ● अंक : 229 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

दिल्ली से प्रकाशित मंगलवार 09 जून 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

गरीबों और वंचितों के कल्याण को समर्पित रहे पिछले 12 वर्ष : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई परिवर्तनकारी बदलावों का अनुभव किया है और इन सभी प्रयासों के केंद्र में गरीबों, वंचितों तथा जरूरतमंद वर्गों का कल्याण रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर कार्य कर रही है, जिसके तहत विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना भी है।

अंत्योदय की भावना से संचालित रही विकास यात्रा : प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना रहा है। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक माना जा सकता है जब उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो लंबे समय तक मुख्यधारा के विकास से वंचित रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिनसे आम नागरिकों के जीवन स्तर में प्रत्यक्ष सुधार हो और उन्हें बुनियादी सुविधाएं सुलभ हो सकें।

जनकल्याणकारी योजनाओं से मजबूत हुई सामाजिक सुरक्षा : प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिला है। इससे न केवल उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी व्यापक हुआ है।

तकनीक ने बढ़ाई पारदर्शिता और दक्षता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और डीबीटी व्यवस्था के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। उनके अनुसार, तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका में कमी आई है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है और शासन व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई पहलें अब केवल सरकारी योजनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि वे मानव सशक्तिकरण का व्यापक अभियान बन चुकी हैं। इन प्रयासों ने लाखों परिवारों को नई संभावनाएं प्रदान की हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयास देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है, ताकि कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से पीछे न रह जाए।

'गरीब कल्याण योजना' मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि 'गरीब कल्याण योजना' हमेशा से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "सरकार ने इन 12 वर्षों में करोड़ों नागरिकों को अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास, जन-धन, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर 'विकसित भारत' की मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

पश्चिम बंगाल की राजनीति और गैंगस्टर राजनीति की तुलना

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह रही है कि सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से होता है, न कि भय, हिंसा या दबाव के जरिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक हिंसा, दलगत संघर्ष, जांच एजेंसियों के उपयोग को लेकर उठते सवाल और मीडिया की भूमिका पर बढ़ती बहस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन चर्चाओं के केंद्र में रही है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का गढ़ माना जाता रहा है। पहले वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आती थीं, जबकि हाल के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव लगातार सुर्खियों में रहा है।

चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसा, पार्टी कार्यालयों पर हमले, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं तथा विरोधी दलों के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं पर समय-समय पर अदालतों और चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों को लगातार दबाव, भय या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तब राजनीति का चरित्र लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा से हटकर शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगता है। इसी संदर्भ में कुछ आलोचक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना संगठित गिरोहों की कार्यप्रणाली से करते हैं। हालांकि यह तुलना एक राजनीतिक राय है और इसे तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

दाऊद इब्राहिम भारत का एक कुख्यात अपराधी रहा है, जिस पर संगठित अपराध, तस्करी, वसूली और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोप लगे। उसकी कार्यप्रणाली भय, दबाव और नेटवर्क आधारित नियंत्रण पर आधारित बताई जाती रही है। दूसरी ओर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिन्हें जनता के मतों से वैधता प्राप्त होती है। इसलिए किसी राजनीतिक दल की सीधे किसी आपराधिक गिरोह से तुलना करना एक गंभीर राजनीतिक आरोप है, जिसके समर्थन में ठोस न्यायिक या कानूनी निष्कर्ष आवश्यक होते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों तथा पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को लेकर कई बार आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि उसके कार्यकर्ता राज्य में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में भी राजनीतिक हिंसा को राज्य की गंभीर समस्या बताया गया है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

सरकार का दावा- देश में पेट्रोल-डीजल और घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त भंडार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट के बादजूद

कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। सरकार ने बताया कि हमारे पास देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम. खानूजा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा हालात के बावजूद कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। घरेलू रिफाइनरियों और फ्रैक्शनटर्स से एलपीजी का घरेलू उत्पादन अधिकतम स्तर पर है। वे रोजाना लगभग 52-53 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) उत्पादन कर रहे हैं, जो संकट से पहले के स्तर से लगभग 60 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही एलपीजी डिलीवरी का बैकलॉग घटकर 4 दिन से भी कम हो गया है, जबकि 99 फीसदी एलपीजी सिलेंडर बुकिंग अब ऑनलाइन होती हैं। वहीं, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) का अनुपालन रेट लगभग 96 फीसदी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइज़र की खरीद 86.65 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई है, जो कुल जरूरत का 22.57 फीसदी है।

पाकिस्तानी पुलिस पर टूट पड़ी जनता, 5 को मार डाला

मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में इस समय हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं और आम जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रविवार देर रात एक प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार के दौरान पाकिस्तानी सेना और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प ने आग में घी का काम किया है। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने जनाजे में शामिल लोगों पर बल प्रयोग किया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस ताजा हिंसा के बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह घेर लिया है। क्षेत्र में भड़की हिंसा में अब तक कुल 8 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रावलकोट और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। यह बवाल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेतृत्व में हो रहा है, जिसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संगठन ने आगामी 9 जून को एक ऐतिहासिक महाआंदोलन और बड़े मार्च का ऐलान किया है, जिससे चुनाव से ठीक पहले माहौल और अधिक हिंसक होने की आशंका है। दूसरी ओर, सरकार ने इस संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए इसे अराजकता फैलाने वाला समूह घोषित किया है।

सीबीएसई ने रिजल्ट पोर्टल पर उठे सवालों को किया खारिज, तकनीकी खराबी नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं के पोर्टल के संचालन को लेकर सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों पर सोमवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित हुई। इस दौरान 1.6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित अनुरोध दर्ज किए। बोर्ड के अनुसार इस अवधि के दौरान सरकारी तकनीकी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की विशेषज्ञ टीमों की निगरानी में पोर्टल का संचालन किया गया। पोर्टल को साइबर हमलों और अन्य ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा टीमों ने पूरे समय निरंतर निगरानी की। इसके अलावा छात्रों की सहायता के लिए

सीबीएसई की हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण प्रणाली भी सक्रिय रही। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट देखते समय 'रोल नंबर नॉट फाउंड' संदेश का कारण तकनीकी खराबी नहीं था। यह संदेश उन अभ्यर्थियों को प्रदर्शित हुआ, जिन्होंने पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया के पहले चरण, यानी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया था। सीबीएसई के अनुसार केवल वही छात्र सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की अगली प्रक्रिया के लिए पात्र थे, जिन्होंने पहले चरण में उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी/स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया था।

इंडिया ब्लॉक की सातवीं अहम बैठक में विपक्षी एकजुटता पर जोर

- राहुल, ममता, अखिलेश समेत शीर्ष नेता शामिल
- शरद पवार बोले- साथ रहना समय की जरूरत

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक की सातवीं अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठक से ऑनलाइन जुड़े। बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के 23 घटक दल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दौरान विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सभी सहयोगी दलों का साथ रहना आवश्यक है। उनके बयान को विपक्षी एकता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर विपक्षी दलों की एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प को दोहराया। इस बीच, अनजाने विरोधियों ने बैठक के दिन दिल्ली की अकबर रोड पर राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर विवादित पोस्टर लगा दिए थे। सुबह लगाए गए इन पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कांग्रेस विरोधी टिप्पणियां लिखी गई थीं। कुछ पोस्टरों में शरद पवार की तस्वीर का उपयोग करते हुए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने वाले संदेश भी दर्ज थे। हालांकि पोस्टर लगाने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। दोपहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इन पोस्टरों को हटा दिया। गौरतलब है कि इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक 1 जून 2024 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी। लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद गठबंधन के सभी प्रमुख नेता एक मंच पर एकत्र हुए हैं, जिससे आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

भारत ने पश्चिम एशिया में सभी पक्षों से तनाव कम करने का किया आग्रह

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में सभी पक्षों से आग्रह किया कि वह तनाव को कम करने, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और राजनयिक समाधान तलाशने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली बेहद जरूरी है। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया के ताजा हालात वैश्विक मुदाय के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है। क्षेत्र में जारी संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में तेजी आई है। ईरान ने इजराइल के महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने पश्चिम और मध्य ईरान में सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है। इसी बीच ईरान और इजराइल स्थित भारतीय दूतावासों ने परामर्श जारी कर भारतीयों को ईरान नहीं जाने और इजराइल की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को तुरंत वहां से किसी भी माध्यम से निकलने को कहा है। वहीं इजराइल में रह रहे भारतीयों को सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

इजरायल ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, कई सैन्य ठिकाने तबाह

तेहरान। मध्य पूर्व में जारी तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सोमवार को ईरान के कई इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। इस सैन्य कार्रवाई में ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने एहतियातन अपने सबसे प्रमुख हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। यह आक्रामक कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बेहद बढ़ गई है, जबकि कुछ ही समय पहले तक यह माना जा रहा था कि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के

मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों इश्फाहान, तबरीज और राजधानी तेहरान में सिलसिलेवार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसके अलावा, पश्चिम तेहरान के करज इलाके में भी भारी विस्फोट होने की खबरें हैं। इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि वायुसेना ने कुछ समय पहले ही पश्चिम और मध्य ईरान में स्थित चुनिंदा सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है।

हालिया संकेतों से बढ़ीं अटकलें, मोदी कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दो साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल और विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के हालिया संगठनात्मक और रणनीतिक कदमों ने इन कयासों को हवा दी है। इन कदमों में दो केंद्रीय मंत्रियों को राज्य इकाइयों की अहम जिम्मेदारी सौंपना और दो अन्य को राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकित न करना शामिल है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तब और बढ़ गई जब भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए पांच राज्यों से 11 नेताओं को नामांकित किया, लेकिन इस सूची से दो केंद्रीय

मंत्रियों—रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का नाम गायब रहा। इन दोनों मंत्रियों की राज्यसभा सदस्यता 21 जून को समाप्त हो रही है। पंजाब से कांग्रेस के पूर्व सांसद बिट्टू वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि केरल के मूल निवासी कुरियन मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण की थी। इस मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकालों के दौरान भी सरकार के दो साल पूरे होने के ठीक बाद जुलाई 2016 और जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद का फेरबदल और विस्तार किया गया था। इस बार भी वैसा ही पैटर्न दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है। संवैधानिक नियमों के अनुसार, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत हो सकता है।

न्यू हेवन में सुरक्षा बल का बंकर ध्वस्त

- मणिपुर में असम राइफल्स का विरोध
- जवानों का दावा- महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की

एजेंसी। उखरुल

मणिपुर के उखरुल जिले के शोक्वाओ और न्यू हेवन इलाके में सैकड़ों महिलाएं असम राइफल्स के जवानों और वाहनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। मशालें, लाठियां लिए ये तंग्खुल नगा महिलाएं जवानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं। सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी। इसके बावजूद वे डटी रहीं और 'हमारी जमीन, हमारा अधिकार' नारे लगाती रहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जवानों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की गैरमौजूदगी में कई राउंड हवाई फायर किए और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से धक्का-मुक्की भी की गई। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में जवानों ने दावा किया है कि विरोध कर रही महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में

एक प्रदर्शनकारी के पैर पर गोली लगने का दावा किया गया। वहीं, 22 महिलाएं घायल हो गईं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक शोक्वाओ गांव की महिलाओं ने न्यू हेवन की ओर बढ़ रहे काफिले को देर रात ही रोक लिया था। इससे रातभर तनाव रहा। सुबह होते ही एक समूह ने शोक्वाओ पर ब्लॉकेड बनाया, तो दूसरे ने न्यू हेवन में सुरक्षा बल का बंकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि असम राइफल्स ने शोक्वाओ की विलेज अथॉरिटी की सहमति के बिना न्यू हेवन में अस्थायी बंकर बनाया। घटनाक्रम के बाद से शोक्वाओ-न्यू हेवन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि असम राइफल्स को तुरंत वापस बुलाया जाए, वरना अप्रिय घटना की जिम्मेदारी उनकी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने मणिपुर में तैनात जवानों को निर्देश दिया है कि नागरिक इलाकों में सक्रिय सशस्त्र मिलिटेंट्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें। बता दें दो कोबरा बटालियन यहां जल्द आने वाली हैं। तंगखुल उत्तर-पूर्व भारत के प्रमुख नगा समुदायों में से एक हैं। वे मुख्य रूप से मणिपुर के उखरुल और कामजोंग जिलों में रहते हैं। उनकी आबादी का एक हिस्सा म्यांमार के सोमरा क्षेत्र में बसता है।

राष्ट्रपति 23 जून को 65 प्रतिष्ठित लोगों को प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति ने इससे पूर्व 25 मई को पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाला यह समारोह देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

संक्षिप्त समाचार

टीएमसी से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर राय ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी नेतृत्व जनता से पूरी तरह कट गया और संगठन में पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह भ्रष्ट तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दिया गया। राय ने सोमवार को दिए इस्तीफे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 15 वर्षों के शासन की आलोचना करते हुए कहा कि हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में जनता ने अभूतपूर्व मतदान कर सत्ता परिवर्तन का निर्णय लिया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने चुनावी पराजय के कारणों का गंभीरता से विश्लेषण तक नहीं किया।उन्होंने कहा कि सत्ता के लंबे दौर ने पार्टी नेताओं को आम लोगों से दूर कर दिया। पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों तक आम नागरिकों की पहुंच मुश्किल हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संघर्ष कर संगठन को मजबूत किया, उन्हें हाशिये पर धकेल दिया गया और उनकी जगह बिचौलियों, भ्रष्ट तत्वों तथा आपराधिक छवि वाले लोगों को महत्व दिया गया। राय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों में असामान्य वृद्धि देखने को मिली। जनता के बीच इसको लेकर व्यापक असंतोष था। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया था। बड़ी संख्या में नागरिक, चिकित्सक और विभिन्न वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ दल ने जनता की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। जनता ने जिस विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी, उसी जनता ने बाद में सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने नई सरकार से पिछले पांच वर्षों के दौरान अस्पतालों में हुई खरीद प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधियों और नेताओं की संपत्तियों की जांच कराने की मांग की। भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राय ने कहा कि सत्ता के अहंकार में यह मान लिया गया था कि कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।

साकेत में इमारत गिरने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, एमिकस क्यूरी ने एमसीडी को दोषी ठहराया

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के मामले पर उच्चतम न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। अवैध निर्माण को लेकर नियुक्त एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दाखिल की है। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम की ओर से लगातार अनदेखी और लापरवाही की वजह से

इमारत गिरी है। रिपोर्ट में भवन कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट में दिल्ली में अवैध निर्माणों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में हादसे की जवाबदेही तय करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। रिपोर्ट में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी का कहना है कि दिल्ली नगर निगम की लापरवाही की वजह से साकेत इलाके में बिल्डिंग गिरी जिसमें छह लोगों की मौत हुई। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 30 मई को सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत गिर गई। इमारत पास की कैंटीन पर गिरी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला और वे मलबे के नीचे दब गए।

टीएमसी में टूट की अटकलें तेज, भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे सुखेंदु शेखर सहित 14 सांसद

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) टूटती नजर आ रही है। पहले टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बनाया और अब यह टूट संसदीय दल तक पहुंच गई है। टूट की अटकलों के बीच सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के करीब 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के घर पहुंचे और बंद कमरे में बैठक की। बैठक में राज्यसभा की

सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर भी शामिल हुए। सुखेंदु ने आज ही राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देब भी मौजूद रहे। इस राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले सुखेंदु शेखर ने मीडिया से बातचीत में आरजी कर अस्पताल मामले में तृणमूल कांग्रेस के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने राय रखी थी। तब से पार्टी के भीतर उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। सुखेंदु ने कहा कि उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की थी क्योंकि मेरा मानना था कि सबूतों को नष्ट करने में उनकी अहम भूमिका थी। इसके कारण उन्हें पार्टी से अलग थलग कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि संसद में दलबदल विरोधी कानून को दरकिनार करने के लिए बागी गुट को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है।तृणमूल कांग्रेस के पास वर्तमान में लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष औऱ विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कुछ संगठनात्मक फेरबदल किए। चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सुब्रता बख्शी की जगह ली है। खास बात यह है कि बैठक में बागी खेमे से कोई भी उपस्थित नहीं था। बैठक में मदन मित्रा, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, अशोक देब, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अभिषेक बनर्जी जैसे पुराने नेता ही मौजूद थे।

मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल में ईडी की छापेमारी, 142 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन का मामला

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में चार जगह पर छापेमारी की। जांच में अब तक 142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का पता चला है। मामला म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से संबंधित है।ईडी के आइजोल उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत यह कार्रवाई की। यह जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की अगरतला जोनल यूनिट द्वारा दर्ज मामले पर आधारित है। इस मामले में 21 अगस्त 2025 को त्रिपुरा में 49.101 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।ईडी के अनुसार, जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है, जो म्यांमार से मिजोरम के चम्फाई-जोखावथार क्षेत्र के रास्ते मेथामफेटामिन भारत लाता था। इसके बाद खेप को त्रिपुरा में मौजूद रिसीवरों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि तस्करी से अर्जित धन को कई बैंक खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर छिपाया और स्थानांतरित किया गया। अब तक 142 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध धनराशि की पहचान की जा चुकी है।ईडी ने बताया कि त्रिपुरा में जिन स्थानों पर कार्रवाई की गई, वे बांग्लादेश सीमा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जबकि मिजोरम में छापेमारी का एक स्थान म्यांमार सीमा से लगभग 500 मीटर दूर है। एजेंसी मामले में धन के प्रवाह, तस्करी नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है।

इंडी गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में लगे राहुल गांधी विरोधी पोस्टर, विपक्षी एकता पर उठे सवाल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडी' (आईएनडीआईए) की महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को प्रस्तावित बैठक से पहले शहर के कई प्रमुख इलाकों में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं के पुराने बयानों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिनके माध्यम से कांग्रेस की विश्वसनीयता और गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के अशोका रोड, रेल भवन, ली मेरिडियन गोलचक्कर समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया। पोस्टरों

में कांग्रेस पर अपने सहयोगी दलों के साथ विश्वासघात करने और गठबंधन की राजनीति को कमजोर करने के आरोप लगाए गए हैं। इन पोस्टरों का उद्देश्य यह संदेश देना प्रतीत होता है कि इंडी गठबंधन के भीतर शामिल दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद अब भी मौजूद हैं और कांग्रेस को लेकर सहयोगी दलों में पूरी सहमति नहीं है। पोस्टरों में विभिन्न विपक्षी नेताओं के पुराने कथनों को उद्धृत (कोट) करते हुए कांग्रेस और उसके नेतृत्व को घेरने का प्रयास किया गया है।एक पोस्टर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार का पुराना बयान प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया था कि "राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है।" दूसरे पोस्टर में पिनराई विजयन का बयान छापा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनमें उतनी समझ भी नहीं जितनी कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता में होती है।" इसी प्रकार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) नेता उदयनिधि स्टालिन का बयान भी पोस्टरों में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि "कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और अब उसी पीठ में छुरा घोंप दिया।" पोस्टरों में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के पुराने बयानों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें "कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते" तथा "अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं" जैसे कथन शामिल हैं। कुछ पोस्टरों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों का भी संदर्भ दिया गया है, जिनके माध्यम से कांग्रेस और उसके नेतृत्व की आलोचना की गई है।सभी पोस्टरों के नीचे एक समान नारा लिखा गया है "इंडी अलायन्स वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, वो साथ क्या लड़ेंगे!"इस नारे के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि वह एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकता। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन पोस्टरों को किस संगठन, राजनीतिक दल या व्यक्ति ने लगवाया है। पोस्टरों पर किसी संस्था या समूह का नाम भी नहीं दिया गया है।इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने ये पोस्टर नहीं देखे हैं, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।इंडी गठबंधन की बैठक से पहले वामपंथी दलों की ओर से भी कांग्रेस के प्रति असंतोष के संकेत मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले दलों की संख्या और एजेंडा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वाम दलों के अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, जिन्हें वे बैठक में मजबूती से उठाएंगे। डी. राजा ने यह भी आरोप लगाया कि केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वाम दलों की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, जिससे दोनों पक्षों के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ।इंडी गठबंधन की यह बैठक आगामी चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इसमें लगभग 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में आगामी चुनावी रणनीति, विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे, साझा कार्यक्रम और विपक्षी एकता को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैठक से पहले सामने आए ये पोस्टर विपक्षी एकजुटता की छवि को चुनौती देने का प्रयास हैं। ऐसे समय में जब इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, सहयोगी दलों के पुराने बयानों को लेकर उठी यह बहस गठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। हालांकि बैठक में शामिल दलों की चर्चा और फैसले ही तय करेंगे कि विपक्ष आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना किस तरह करता है।

साइबर ठगी से बचाव के लिए शाहदरा पुलिस की पहल, 250 वरिष्ठ नागरिकों को किया जागरूक

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच शाहदरा जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए सोमवार को मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न इलाकों से करीब 250 वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों ने उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी, फर्जी बैंक कॉल, ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई ठगी और सोशल मीडिया धोखाधड़ी जैसे नए साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था, जोन-1) देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त अजीत कुमार सिंगला और शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराधी लोगों के भरोसे, डर और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर ठगी कर रहे हैं,

इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाए साइबर अपराध के तरीके:कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण साइबर अपराध पर आधारित नुक्कड़ नाटक रहा। कलाकारों ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस कॉल, ओटीपी ठगी, निवेश घोटाले, सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर ठगी और यूपीआई फ्रॉड जैसी घटनाओं का मंचन किया। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बताया गया कि अपराधी किस तरह लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खातों से रकम उड़ा देते हैं।

इन साइबर ठगी के तरीकों से किया आगाह:पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस व बैंक अधिकारियों के फोन, केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी, ऑनलाइन निवेश घोटालों, कॉल मर्जिंग स्कैम, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और यूपीआई फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने सलाह दी कि किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम पिन, सीवीवी नंबर और इंटरनेट बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही अज्ञात लिंक पर क्लिक करने और अनजान लोगों के कहने पर मोबाइल में कोई एप डाउनलोड करने से बचें।

1930 पर तुरंत करें शिकायत:कार्यक्रम में बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या [राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल](https://www.cybercrime.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर शिकायत दर्ज करें। अधिकारियों ने कहा कि समय रहते शिकायत करने पर ठगी की रकम को फ्रीज कराने और अपराधियों तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

"सोच-समझकर क्लिक करें":कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी धमकी भरे फोन कॉल से घबराएं नहीं, पैसे मांगने वाले हर संदेश की पुष्टि करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं।

कार्बन उत्सर्जन एवं हरित ऊर्जा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित, विशेषज्ञों ने दिए पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण सुझाव

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में पर्यावरणीय संस्था ग्रीन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सामाजिक संस्था आश्रय अधिकार अभियान के संयुक्त तत्वावधान में "कार्बन उत्सर्जन एवं हरित ऊर्जा" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्रीन इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं राष्ट्रीय सचिव श्री शमसुद्दीन ए. के. ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सहभागिता कर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सिराजुद्दीन अहमद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की वैज्ञानिक डॉ. शिखा ई. जॉन, दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. अनिल कुमार, श्री आर. के. यादव, पीपुल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. पी. हरिंदर अचारी तथा आश्रय अधिकार अभियान के निदेशक डॉ. संजय कुमार ने अपने विचार रखे। विशेषज्ञों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा के बढ़ते महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की और उपस्थित प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर विषय आधारित एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और APCR के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने तोपसिया और बंगाल के अलग-अलग जिलों का दौरा किया

» बुलडोजर कार्रवाई का सामना कर रहे पीड़ितों से मुलाकात और कानूनी सुरक्षा की मांग की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और APCR का एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान, एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष डॉ. मसीह-उर-रहमान और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय लोगों से मुलाक़ातें कीं और जनहित के मुद्दे खासकर तोपसिया में प्रस्तावित बुलडोज़र कार्रवाई को रोकने पर चर्चा की। ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद तोपसिया में बुलडोज़र कार्रवाई

की कोशिश की गई थी। जनता के विरोध और कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद इस कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया ।इसके बावजूद, हज़ारों घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। विध्वंस की इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पर्याप्त उपाय न होने के कारण अब लगभग 15,000 लोगों के विस्थापित और बेघर होने का ख़तरा पैदा हो गया है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और APCR ने बंगाल सरकार की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई और तोपसिया के निवासियों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित विध्वंस के मामले में उन्हें हर संभव कानूनी और नैतिक समर्थन दिया जाएगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर यमुना तट पर वृक्षारोपण एवं जागरूकता रैली का आयोजन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा आश्रय अधिकार अभियान के संयुक्त तत्वावधान में मयूर विहार फेज-1 के सामने यमुना तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के प्रति आमजन को जागरूक करना था। इस अवसर पर यमुना किनारे कृषि कार्य करने वाले किसानों, उनके परिवारजनों, छात्र-छात्राओं, आवास कल्याण संगठनों से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं वृक्षों के महत्व से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वृक्षारोपण न केवल हरित

वातावरण का निर्माण करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता बनाए रखने तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जनभागीदारी ही सबसे बड़ा माध्यम है और ऐसे अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

'एक्ट ईस्ट' को नई रफ्तार: भारत-इंडोनेशिया के बीच रक्षा-व्यापार पर महामंथन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो 6 से 8 जून तक भारत के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष डॉ० एस० जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में आयोजित 8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता की, जो लगभग चार साल के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत-इंडोनेशिया 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के तहत सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सामरिक हलकों में इस यात्रा को लेकर इसलिए भी उत्सुकता है, क्योंकि हाल के महीनों में भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की संभावित खरीद को लेकर बातचीत तेज हुई है। इस दौरान विदेश मंत्री सुगियोनो ने पुष्टि की है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में जकार्ता का दौरा करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा दोनों मंत्रियों ने राजनीतिक, रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, शिक्षा, कांसुलर और सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत - जिसमें जनवरी 2025 में राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हुई बातचीत भी शामिल है - ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की है। दोनों मंत्रियों की बैठक में कूटनीतिक चर्चा के साथ दोस्ताना माहौल भी देखने को मिला, जब इंडोनेशियाई विदेश मंत्री ने भारत आने को लेकर मजाकिया टिप्पणी की। बैठक के दौरान सुगिओनो ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं हमेशा भारत आने का कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता हूं।'' उनके इस बयान पर बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल के अन्य लोगों के बीच हल्का-फुल्का माहौल बन गया। भारतीय विदेश मंत्री ने भी चुटीले अंदाज में जवाब दिया,

जिससे इंडोनेशियाई विदेश मंत्री हंस पड़े। दोनों नेताओं के बीच हुई यह दोस्ताना बातचीत सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई और कूटनीतिक बैठकों के बीच सहज माहौल की झलक देखने को मिली। इंडोनेशिया भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक प्रमुख स्तंभ है। गहरे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित, भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी सहयोग के स्थापित और नए क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रही है।

परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट ने सीबीएसई को जारी किया नोटिस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में हुई गड़बड़ियों और ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) से जुड़ी शिकायतों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को करने का आदेश दिया। यह याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की ओर से इसके अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दायर की है। सुनवाई के दौरान सीबीएसई के वकील एमए नियाजी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने दायर किया है। शिक्षा का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस पर एनएसयूआई के वकील ने कहा कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े

हुए हैं, लेकिन ये इस बात की वजह नहीं हो सकती कि वे याचिका दायर करने के योग्य नहीं हैं। सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल एक महीने के लिए नहीं खोला जा सकता। सीबीएसई छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रही है।याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों के कम अंक आए हैं या स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त नंबर दिए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि वेरिफिकेशन के लिए नया विंडो, विवादित आंसर शीट की दोबारा फिजिकल जांच और 12वीं के रिजल्ट पर असर डालने वाली कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। याचिका में भविष्य के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए सही सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई हैं, ताकि ऐसी शिकायतें दोबारा न हो।

संक्षिप्त समाचार

रहरा में नाबालिग से दुष्कर्म, एसपी ने किया मौका मुआयना, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुर/रहराः थाना रहरा क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का निरीक्षण किया।एसपी लखन सिंह यादव ने मौके पर मौजूद थाना प्रभारी व अन्य अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और जांच में बरती जाने वाली हर तकनीकी पहलू पर निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही हर संभव मदद और त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा,एसपी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले की विवेचना पूरी निष्पक्षता और तेजी से की जाए। नामजद अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।पुलिस ने घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद पुलिस इस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। महिला व बच्चियों के खिलाफ अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दोषी की गिरफ्तारी कर सख्त से सख्त सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर आप चिन्तित

लोक तंत्र की शान : बांदा । आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष समरजीत सिंह ने जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। आप जिलाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में कहा कि लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता साथियों पर अचानक किए गए लाठी चार्ज एवं हाथ में रामचरितमानस लिए हुए अधिवक्ता पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई। आम आदमी पार्टी अधिवक्ता प्रकोष्ठ एडवोकेट भूपेंद्र शुक्ला एवं बांदा यूनिट इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं तथा बांदा के समस्त अधिवक्ता साथियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डीएम बांदा से अनुरोध करते हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वसूलना कॉपी किताबें, बैग एवं जूता एवं अन्य सामग्री , भारी भरकम कमीशन के चक्कर में स्कूल द्वारा बताए गए दुकान से ही लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य करना। जिससे गरीब आदमी इस महंगाई में कैसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकता है। मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर द्वारा बाहर अपने महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना तथा गरीब आदमी की पूरी पूंजी का शोषण करना। अन्य मांगों का उल्लेख करते हुये कहा कि जिला कारागार बांदा में नीतीश पाल की असामयिक मृत्यु से पाल समाज में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। केन नदी में हो रहे अवैध खनन से केन नदी का सीना छलनी करने वाले खनन माफियाओं पर कार्यवाही एवं केन नदी को टूरिस्ट प्लेस घोषित करते हुए उसमें नाइट शो एवं नौकविहार की सुविधा बांदा वासियों को दी जाये। एवं केन नदी के पुल के ऊपर जाल लगाया जाए।जिससे लोग नदी में कूद कर आत्महत्या ना करें। आज के इस कार्यक्रम में जिला महासचिव डॉक्टर अमित कुशवाहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शुक्ला, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार सविता,जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार दद्दा, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत कलीम भाई, जिला सचिव अमित गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष इंजीनियर संदीप तिवारी,आदि साथी उपस्थित रहे।

महंगाई, पेपर लीक और किसान मुद्दों पर सपा का प्रदर्शन

डीएम कों केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान : उरई (जालौन)। समाजवादी पार्टी जनपद जालौन के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय से अम्बेडकर चौराहा,जिला परिषद होकर पैदल मार्च तथा नारेवाजी करते तथा हाथों में श्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां पर जोरदार नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक होने, बिजली बिल, रोजगारी , किसानों की समस्याएं आदि तमाम मुद्दों को लेकर जिला अधिकारी राजेश पांडे को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सोपा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने कहा कि जनपद जालौन बुंदेलखंड क्षेत्र का पिछड़ा हिस्सा है। यहां 90% आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसान, नौजवान, बेरोजगार आदि डीजल पेट्रोल गैस की बढ़ती महंगाई और पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल 100 रूपये प्रति लीटर पार कर चुका है। कुछ दिनों के अंतराल में ही 10 रूपया प्रति लीटर की वृद्धि हुई है ।वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 12 वर्षों में इस भाजपा की सरकार में दुगने से अधिक महंगा हो गया है। किस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

यूपीडा के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के विरोध में गंगवार में किसान महापंचायत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/गंगवारः यूपीडा द्वारा औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में सोमवार को ग्राम गंगवार में किसानों की बड़ी बैठक चौधरी मजाहिर हुसैन व गुड्डू प्रधान के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता मुजाहिद चौधरी ने की, जबकि संचालन परवेज आलम उर्फ गुड्डू प्रधान ने किया। बैठक में मुजाहिद चौधरी ने प्रस्तावित अधिग्रहण को अनावश्यक और उत्पीड़क कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गंगवार, हाकमपुर समेत पतेई खादर, बुरावली, बांसका कलां, मटीपुरा, दौलतपुर, रूस्तमपुर और गांगटकोला की भूमि बेहद उपजाऊ है। यहां गेहूं, गन्ना, धान की बंपर पैदावार होती है। ऐसी जमीन पर उद्योग लगाना अव्यवहारिक और किसानों के साथ अन्याय है। किसानों ने आरोप लगाया कि तहसील हसनपुर में वन विभाग की हजारों बीघा अनुपजाऊ और बंजर भूमि खाली पड़ी है। सरकार को उद्योग वहीं स्थापित करने चाहिए। उपजाऊ जमीन छीनकर किसानों को बेरोजगार करना स्वीकार नहीं होगा। बैठक में सातों गांवों की सर्किल दरें बढ़ाने की पुरजोर मांग उठाई गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि अधिग्रहण के विरोध और सर्किल रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। पांच सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम व सब रजिस्ट्रार हसनपुर, जिलाधिकारी अमरोहा, राजस्व परिषद, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, भारतीय किसान यूनियन और सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इनसे मिलकर सहयोग मांगेगा। बैठक में अफसार अहमद, शफात हुसैन, रियाजुद्दीन, मोहम्मद वारिस, कारी कमरूल इस्लाम, इरफान अहमद, हाजी मजाहिर हुसैन, हाजी भुर्रन, नवेद आलम, मेराजुद्दीन, मास्टर मुन्ना, छोटे भाई, बाबू भाई, नियामतुल्लाह, जीशान सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जबरन अधिग्रहण की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन होगा।

यूपी के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को साइंटिफिक तरीके से बढ़ाएगा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किए गए कार्यों के परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। महज 11 फीसदी कृषि योग्य भूमि में यूपी देश का 21 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन करता है। समय पर मौसम, बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि की जानकारी नहीं मिलेगी तो हम किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना मौसम की और सटीक जानकारी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह संग बटन दबाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हम लोग सीजन में अतिवृष्टि-अनावृष्टि, आकाशीय बिजली आदि के संबंध में मेट्रोलॉजिकल व अन्य विभागों की बैठक में चर्चा करते थे कि समय पर सटीक जानकारी मिलने से सही रणनीति संभव होती है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में लखनऊ खुद को मेट्रोलॉजिकल रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित कर रहा है। ग़ह यूपी के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के प्रति आभार भी जताया।

किसी भी निर्धन या जरूरतमंद की शिक्षा को बाधित नहीं होने देगी सरकारः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। एक बच्ची ने मुख्यमंत्री से उच्च शिक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने लखनऊ के किसी संस्थान में प्रवेश दिलाने का आदेश दिया। पुलिस की अनसुनी व अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर सख्त सीएम योगी ने अफसरों को मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का आदेश दिया।

बूढ़ी मां संग आई बेटी, खुश होकर लौटी – लखनऊ की एक बच्ची अपनी बूढ़ी मां के साथ पहुंची। उसने बताया कि इंटरमीडिएट अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है। वह आगे बीटेक करना चाहती है, लेकिन धन के अभाव में दिक्कत हो रही है। सीएम योगी ने उसकी मार्कशीट देखी, फिर कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। आपका प्रवेश किसी अच्छे संस्थान में कराया जाएगा। सरकार किसी भी निर्धन या जरूरतमंद की शिक्षा को बाधित नहीं होने देगी। सकारात्मक संदेश पाकर प्रफुल्लित बेटी व मां ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

अवैध कब्जे की शिकायत पर अफसरों से बोले– 'मॉनीटरिंग कर पीड़ितों को न्याय दिलाइए' –विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से पुलिस की हीलाहवाली व अवैध कब्जे को लेकर उचित कार्रवाई न होने की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने हर प्रकरण को सुना, फिर शासन के अफसरों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि इन मामलों की मॉनीटरिंग करिए। पीड़ित को न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। सीएम ने पीड़ितों को जल्द ही समाधान के लिए आश्वस्त किया।

राजस्व निरीक्षकों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा : अरविंद कुमार शर्मा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः सोमवार को उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ की एक बैठक नवीन तहसील के सभागार कक्ष में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अरविंद कुमार शर्मा ने की, बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्व निरीक्षकों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई गई, बैठक के दौरान जिला अधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र भी तैयार किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई, प्रमुख मांगों में अपर जिला अधिकारी न्यायिक द्वारा राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग पर तत्काल रोक लगाना शामिल है, संघ ने विभागीय परीक्षा पास कर चुके निरीक्षकों को तत्काल स्थाई करने और निलंबित चल रहे राजस्व निरीक्षक सुहेल अख्तर खान को बहाल करने की भी मांग रखी, इसके अतिरिक्त फील्ड वर्ग को सुचारू बनाने के लिए चैनमैंन की नियुक्ति और तहसील के कंप्यूटर भूलेख विभाग में पर्याप्त कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की मांग की गई, साथ ही तहसीलों में राजस्व निरीक्षकों से देर रात तक जवरन कार्य कराने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई, राजस्व निरीक्षकों के दो वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें स्थाई किया जाए आदि मांगे रखी गई, संघ के पदाधिकारीयो ने चेतावनी दि है कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, बैठक की अध्यक्षता अरविंद कुमार शर्मा की तथा संचालन धीरे सिंह ने किया, इस मौके पर मनोज मोपन, देवराज सिंह, विनय कुमार, जबर सिंह, चंद्रपाल सिंह, हरवीर सिंह, रोहतासपास सिंह आदि सहित दर्जनों की संख्या में राजस्व निरीक्षक शामिल हुए 1

भीषण गर्मी में राहत बन रहा पार्थ गौतम फाउंडेशन निस्वार्थ जल सेवा से हजारों लोगों को मिल रही राहत

» मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और प्रमुख चौराहों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था; जनता दरबार के माध्यम से भी सुन रहे लोगों की समस्याएं

लोक तंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच बरेली शहर में मानव सेवा का एक सराहनीय उदाहरण देखने को मिल रहा है। पार्थ गौतम फाउंडेशन द्वारा शहर में निस्वार्थ भाव से व्यापक स्तर पर जल सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे हजारों राहगीरों और आम नागरिकों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस सामाजिक अभियान का नेतृत्व बरेली के मेयर उमेश गौतम के सुपुत्र पार्थ गौतम कर रहे हैं। फाउंडेशन की ओर से शहर के विभिन्न धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर शीतल एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों के साथ-साथ प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए जल सेवा केंद्र लोगों के लिए राहत का माध्यम बने हुए हैं। गर्मी के इस कठिन दौर में राहगीरों, मजदूरों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को निशुल्क ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसे समय में इस प्रकार की जनसेवा समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करती है। पार्थ गौतम फाउंडेशन द्वारा यह जल सेवा अभियान कोई नई पहल नहीं है। संस्था पिछले कई वर्षों से गर्मी के मौसम में लगातार इस सेवा कार्य का संचालन करती आ रही है। हर वर्ष हजारों लोग इस अभियान से लाभान्वित होते हैं और लोगों के बीच फाउंडेशन की पहचान एक सक्रिय सामाजिक संस्था के रूप में मजबूत हुई है। जल सेवा के अलावा पार्थ गौतम सामाजिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जरूरतमंदों की सहायता, संकटग्रस्त परिवारों तक सहयोग पहुंचाना और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहभागिता उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी व्यक्ति के संकट की सूचना मिलने पर फाउंडेशन द्वारा तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। फाउंडेशन कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित होने वाला जनता दरबार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जहां उनकी बात सुनी जाती है और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से संपर्क कर समाधान का प्रयास किया जाता है। कई जरूरतमंद और पीड़ित परिवारों को इस पहल से राहत मिलने की बात सामने आई है।

कुपोषण के खिलाफ जंग में यूपी बना मॉडल, 1.56 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रहा पौष्टिक आहार

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश के लिए एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की सक्रिय कार्यशैली के चलते प्रदेश में संचालित टेक होम राशन योजना मातृ एवं शिशु पोषण को नई मजबूती प्रदान कर रही है। पोषण, तकनीक, पारदर्शिता और महिला सशक्तीकरण को एक साथ जोड़ने वाली यह व्यवस्था अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त कर रही है। योगी सरकार ने भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 गाइडलाइन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2023 के अनुरूप रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस नई प्रणाली को बड़े पैमाने पर धरातल पर उतारा है। वर्तमान में प्रदेश में हर महीने लगभग 1.56 करोड़ लाभार्थियों तक पौष्टिक आहार पहुंचाया जा रहा है। इनमें छह माह से छह वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं तथा अतिकुपोषित बच्चे शामिल हैं।

नाटेपन की दर 39.7 से घटकर 31.5 प्रतिशत तक पहुंची –सीएम योगी के मार्गदर्शन में यह पहल केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक असर स्वास्थ्य संकेतकों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-21 के दौरान प्रदेश में बच्चों में स्टंटिंग यानी नाटेपन की दर 39.7 प्रतिशत से घटकर 31.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके अलावा अल्पवजन और दुबलापन जैसी समस्याओं में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि योगी सरकार की पोषण नीति जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणाम दे रही है।

भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक संपन्न गांव-गांव सदस्यता अभियान तेज करने का संकल्प

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा : सोमवार को भारतीय किसान संघ जनपद अमरोहा की विकास खंड जोया इकाई की मासिक व संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में कैलसा बॉर्डर स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक तीन सत्रों में संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार और प्रत्येक गांव तक जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया,बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं प्रांत युवा प्रमुख संजीव कुमार शर्मा मौजूद रहे। इनके साथ जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ कौशिक, ब्लॉक मंत्री संजीव कुमार चौधरी व ब्लॉक सह मंत्री चमन सिंह मंच पर उपस्थित रहे। जिला प्रभारी का प्रवास ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ कौशिक के आवास ग्राम लोदीपुर बंजारा में रहा।प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने संगठन के विस्तार की रणनीति समझाई। उन्होंने कहा कि किसान संघ को मजबूत बनाने के लिए हर गांव में सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना जरूरी है। किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान ही संगठन की पहचान बनेगा। द्वितीय सत्र में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को पूरे खंड में सदस्यता अभियान चलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ कौशिक को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता तय कर सूची जल्द जिला इकाई को उपलब्ध कराएं, ताकि संगठन की पकड़ बूथ स्तर तक पहुंचे। तृतीय सत्र में ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ कौशिक ने प्रस्ताव रखा कि ब्लॉक कार्यकारिणी के साथ जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को भी 4 से 5 गांवों की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे निगरानी सशक्त होगी और किसानों से सीधा संवाद बढ़ेगा,बैठक में गिरिराज शर्मा, योगेंद्र शर्मा, दुष्यंत कुमार, शांति स्वरूप, प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र, जयपाल सिंह, नरेंद्र कुमार यादव, महेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में फसल बीमा, खाद-बीज, गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या पर भी चर्चा हुई। अंत में सभी ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का संकल्प दोहराया।

डीएम हो तो ऐसाः नौमहला मलिन बस्ती में उतरे सांसद-मेयर-डीएम, खुद लगाई झाड़ू और सुनी जनता की फरियाद

» 'सरकार आपके द्वार' अभियान बना मिसाल, मौके पर ही हुआ शिकायतों का समाधान

लोक तंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा)<केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क एवं सेवा अभियान के तहत रविवार को बरेली की नौमहला मलिन बस्ती में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का संदेश दिया। यहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यालयों की सीमाओं से बाहर निकलकर सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए मौके पर ही कार्रवाई की। कार्यक्रम के दौरान सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और जिलाधिकारी अविनाश सिंह स्वयं नौमहला मलिन बस्ती पहुंचे। उन्होंने सफाई अभियान में भाग लेते हुए हाथों में झाड़ू लेकर गलियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की तथा नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। अधिकारियों की इस सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों ने प्रशासनिक पहल की सराहना की। इस अवसर पर आयोजित 'सरकार आपके द्वार' समाधान शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए। शिविर में पेंशन, स्वास्थ्य, बिजली, राशन, स्वच्छता, नगर विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिनमें से कई शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। नगर निगम की ओर से वार्ड संख्या-09 नौमहला मलिन बस्ती में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नालियों की सफाई, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण के बारे में जागरूक किया।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में लापता महिला का आधा जला शव बरामद, ससुराल वालों पर मर्डर का आरोप

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में 3 दिन से लापता महिला का आधा जला शव बरामद किया गया है। घटना जंदाहा थाना क्षेत्र के महिसौर गांव की है। मृतका की पहचान रीता देवी (37) के रूप में हुई। परिजनों ने रीता के ससुराल वालों पर मर्डर कर शव छिपाने का आरोप लगाया है। रीता देवी 5 जून की रात से लापता थीं। आधे जले शव मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मौके पर पहुंची थाना अध्यक्ष चांदनी सवारियां ने तेज धूप का हवाला देते हुए मृतका के मायके वालों से जल्द शव को उठाने के लिए कहा। उन्होंने परिवार वालों से कहा, "मुझे तेज धूप लग रही है, जल्दी करो" इस बात से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रीता देवी की शादी साल 2007 में पप्पू राय उर्फ नंद किशोर राय से हुई थी। उनके ससुर उपेंद्र राय जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। रीता की भाभी रेखा देवी के अनुसार, पप्पू राय ने किसी विवाद के कारण दूसरी शादी कर ली थी और रीता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। मायके वालों का आरोप है कि इसी वजह से ससुराल वालों ने 5 जून की रात रीता की हत्या कर शव को गायब कर दिया। 6 जून को रीता देवी के मायके वाले महिसौर गांव पहुंचे, तो उन्हें घर पर कोई नहीं मिला और ससुराल वाले फरार पाए गए। मायके वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिसौर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भी तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रीता देवी बखरी बराई गांव निवासी जगत राय की बेटी थीं। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उन्हें बताया था कि रीता देवी ने सल्फर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। हालांकि, अधजला शव मिलने के बाद यह कहानी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। परिजनों के अनुसार, हत्या के बाद शव को घर से लगभग 500 मीटर दूर जलाया गया था। बचे हुए अवशेषों को बोरे में बांधकर 200 मीटर दूर एक गड्ढे में फेंक दिया गया था, जहां से बाद में उन्हें बरामद किया गया।

गंडक नदी में डूबने से युवक की मौत, अंतिम संस्कार के बाद नहाते समय गहरे पानी में गया

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के कौनहारा घाट पर गंडक नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को हुई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर रजौली वार्ड नंबर 6 निवासी स्वर्गीय बिंदा चौधरी के पुत्र उमेश चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, उमेश चौधरी शनिवार शाम को कौनहारा घाट पर एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। दाह संस्कार के बाद वे अन्य ग्रामीणों के साथ गंडक नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के बाद सभी ग्रामीण अपने-अपने घर लौट गए, लेकिन उमेश चौधरी वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और ग्रामीणों, दोस्तों व ससुराल में जानकारी ली, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। रात भर उनकी तलाश जारी रही। रविवार को परिजनों और ग्रामीणों ने दोबारा कौनहारा घाट पहुंचकर स्थानीय लोगों और नाविकों से पूछताछ की। नाविकों ने बताया कि रेत किनारे एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान उमेश चौधरी के रूप में हुई। उनके कपड़े और चप्पल भी उसी स्थान पर मिले, जहां उन्होंने स्नान से पहले उतारे थे। पुलिस आशंका जता रही है कि स्नान के दौरान उमेश चौधरी का पैर फिसल गया होगा और वे गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।

बुजुर्ग महिला बोलीं-सरकारी रिकॉर्ड में मुझे मृत घोषित किया, पेंशन रुकी, दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की 75 साल की पवितर देवी का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जबकि, वह जीवित हैं और अपनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। वो पहले बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की लाभार्थी थीं। पिछले तीन महीनों से उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। जब उन्होंने इसकी जानकारी लेने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि विभागीय सत्यापन जांच के दौरान उन्हें मृत दर्शाया गया है। इसी 'कागजी मौत' के कारण उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए पवितर देवी ने कहा, "मुझे सबने मिलकर कागज पर मार दिया है। सरकारी कर्मियों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि मैं जिंदा हूं। पिछले तीन महीने से वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा है।" उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। इस उम्र में भी वह दूसरों के घरों में चौका-बर्तन का काम करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। सरकारी पेंशन उनके लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा थी, जिसके बंद होने से उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और घोर लापरवाही पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे एक बेहद गंभीर और हास्यास्पद मामला बताते हुए कहा कि एक जीवित महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर देना प्रशासनिक तंत्र की आंखें मूंदकर काम करने की आदत को दर्शाता है। वकील झा ने बताया कि पवितर देवी कई महीनों तक अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। थक-हारकर अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि: 1 पवितर देवी की वृद्धजन पेंशन को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द बहाल किया जाए। 2 इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते डिजिटल डेटा और भौतिक सत्यापन की इन गलती को नहीं सुधारा गया, तो कई अन्य जरूरतमंद और असहाय लोग भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। फिलहाल, यह मामला अब तूल पकड़ चुका है और देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक जागता है और पवितर देवी को कागजों पर दोबारा 'जिंदा' कर उनकी पेंशन शुरू करता है।

कार की टक्कर से मजदूर की मौत, रोड क्रॉस करते वक्त हादसा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी

लोकतंत्र की शान :मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सोमवार को सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई है। कार ने बुजुर्ग को रौंद डाला। हादसे के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर आगजनी करने लगे। लोगों के प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। मृतक की पहचान डुमरी निवासी ज्योधि शाह (60) के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि शेनफोर्ड स्कूल के पास ज्योधि रोड क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोर की थी कि बुजुर्ग कई फीट दूर जाकर गिरे। घटना माधौल बाइपास स्थित डुमरी इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। वृद्ध मजदूर की मौत से नाराज लोगों ने माधौल बाइपास को जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब आधे घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम हटवाया और यातायात को सामान्य कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना में शामिल कार और उसके चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फायरिंग मामले में खान सर ने दायर की जमानत याचिका

लोकतंत्र की शान, पटना

फायरिंग मामले में खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कल यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। गोली चलाने वाले दोनों गार्ड्स की बेल के लिए भी आज अप्लाई किया गया है। कोर्ट में गार्ड्स की जमानत को लेकर ज्ञान बिंदु के वकील की ओर से विरोध किया गया। ज्ञान बिंदु के वकील की ओर से कहा गया है कि इरदातन गोली चलवाई गई थी। भीड़ हटाने के लिए फायरिंग नहीं हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों गार्ड्स की केस डायरी और क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी। दोनों की जमानत पर अब 10 जून को सुनवाई होगी। इधर, रौशन आनंद की जमानत पर भी कल यानी मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान खान के वकील ने बेल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले से इनका आपराधिक इतिहास है।

पुलिस ने खान सर के गार्ड्स के बयान पर उनके ऊपर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। पुलिस की FIR में बताया गया है कि खान सर ने गार्ड्स से कहा था- तुम गोली चलाओ बाकी मैं देख लूंगा।

दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। घटना के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है।

खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी नहीं: खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं। बिहार फायर सर्विस कमांडेट रितेश पांडेय ने कहा, 'खान ग्लोबल स्टडीज को एक 31 मई को नोटिस दिया गया था। आज हमारी टीम फिर से जांच करने गई थी, लेकिन कमियों को दूर करने को लेकर सही प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 15 जून के बाद अगर सभी मानक पूरे नहीं होते तो एक्शन लिया जाएगा।' इससे पहले बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने कहा था, 'तय वक्त में सारे मानक पूरे नहीं किए जाते तो कोचिंग सील करने की कार्रवाई की जाएगी।'

गार्ड्स की बेल पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित अपोजिशन के वकील बोले- जानबूझकर गोली चलवाई

चाचा बोले- खान को सजा मिलनी चाहिए: खान सर के दूसरे चाचा इमरान ने भी कहा 'खान सर शिक्षक नहीं माफिया है, जो बच्चे उनके यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, वो उनको धोखा दे रहे हैं। वो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। गंदे नेचर के हैं और अपने सामने किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। उन्हें पैसे का घमंड है, वो नटवर लाल हैं। अगर उनकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होंगे तो उसको 20 बताता है। वही फायरिंग कराया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए।'

'सबका सम्मान, जीवन आसान' कार्यक्रम में 30 आवेदनों की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सबका सम्मान, जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 08 जून 2026 को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आम जनता से संवाद कार्यक्रम में कुल 30 आवेदनों की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में निम्मी सिंह, कासिमपुर (नवहट्टा) निवासी द्वारा सड़क से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके निष्पादन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा को निर्देशित किया गया। वहीं श्री बबलू कुमार यादव, खजुराहा (सोनवर्षा) निवासी तथा श्री संजय यादव, नौसा (नवहट्टा) निवासी द्वारा भूमि विवाद से संबंधित आवेदन दिए गए, जिनके समाधान के लिए क्रमशः अंचलाधिकारी सोनवर्षा एवं अंचलाधिकारी नवहट्टा को निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त श्री ऋषि कुमार, सहरसा निवासी के आवेदन के निवारण हेतु जिला समादेष्टा, होमगार्ड को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एलपीजी गैस वितरण की अद्यतन स्थिति जारी, लंबित आपूर्ति शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहरसा जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की अद्यतन स्थिति जारी की गई है। विभिन्न गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर वितरण एवं उपलब्धता की समीक्षा की गई। भारत गैस अंतर्गत कार्यरत स्थानीय एजेंसियों द्वारा दिनांक 07 जून 2026 को कुल 1100 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के 2381 भरे हुए गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। बैकलॉग दिनों की संख्या 3.3 तथा औसत बिक्री 1298 दर्ज की गई है। एचपी गैस के तहत स्थानीय एजेंसियों द्वारा 07 जून 2026 को कुल 1568 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया। वर्तमान में 5052 भरे हुए 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं।

बैकलॉग दिनों की संख्या 3.38 एवं औसत बिक्री 1503 है। इंडेन गैस के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियों द्वारा 07 जून 2026 को कुल 2019 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया। वर्तमान में 4585 भरे हुए 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। बैकलॉग दिनों की संख्या 5.85 तथा औसत बिक्री 2101 दर्ज की गई है। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित एजेंसियों को लंबित वितरण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

3 वर्षों का इंतजार खत्म, सहरसा को मिली पहली जिला युवा अधिकारी

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: मेरा युवा भारत (MY Bharat) कार्यक्रम के अंतर्गत करीब तीन वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सहरसा जिले को पहली बार जिला युवा अधिकारी के रूप में तृप्ति जैन की नियुक्ति मिली है। उनके पदभार ग्रहण करने के अवसर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस मौके पर एक स्वयंसेवक ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़े इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति होने से जिले में युवा गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तृप्ति जैन के नेतृत्व में युवा विकास, कौशल निर्माण, सामाजिक सेवा एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार होगा। कार्यक्रम में मनीष चौपाल, , टिंकू मैथिल, संजय वत्स, शिवम आनंद, गुरप्रीत कौर, अंकित कुमार, बेचन कुमार, राजीव कुमार, गुंजन कुमारी सहित कई स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सभी ने नव नियुक्त जिला युवा अधिकारी का स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। युवाओं ने उम्मीद जताई कि इस पहल से जिले में रोजगार, कौशल विकास, खेल, शिक्षा, स्वच्छता एवं

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

सिटीजन फीडबैक में पटना देशभर में तीसरे स्थान पर, 7.05 लाख लोगों ने दिया फीडबैक

लोकतंत्र की शान, पटना

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत आम लोगों से उनके शहर की साफ-सफाई की व्यवस्था पर फीडबैक लिया जा रहा है। पटना शहर सिटिजन फीडबैक में देशभर में तीसरे स्थान पर है। रविवार दोपहर तक के आंकड़ों के मुताबिक, पटना के 7,05,036 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज कराया है। सबसे अधिक 9,03,240 सिटिजन फीडबैक के साथ लखनऊ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इंदौर है, जहां से 8,63,752 लोगों ने अपनी राय दी है।

टॉप-300 शहरों में पटना अकेला शहर: टॉप -300 शहरों में पटना अकेला शहर है, जिसने ये भागीदारी दर्ज कराई है। यह उपलब्धि शहर की साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं पर लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। बिहार के अन्य तीन स्मार्ट सिटी इस मामले में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर को अब तक केवल 6,003 फीडबैक मिले हैं। भागलपुर में यह संख्या 4,828 रही, जबकि बिहारशरीफ की स्थिति सबसे कमजोर दिखी और वहां केवल 901 लोगों ने

फीडबैक दिया।

12,500 अंकों पर होगा मूल्यांकन: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत निकायों का मूल्यांकन कुल 12,500 अंकों के आधार पर किया जाएगा। सर्टिफिकेशन (ODF, Water Plus, Garbage Free City) में 2000 अंक, ऑन-ग्राउंड असेसमेंट में 9500 अंक और सिटीजन फीडबैक में 1000 अंक शामिल हैं।

शहर की साफ-सफाई को लेकर पूछे 13 सवाल: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नागरिकों से शहर की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े 13 सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों में घर-दुकान से कचरा उठाव, सूखा-गीला कचरा सेग्रेगेशन, नियमित सफाई, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, RRR सेंटर की जानकारी, शिकायत निवारण व्यवस्था, आदि विषय शामिल हैं।

♦ टॉप-300 शहरों में बिहार से सिर्फ पटना शामिल

कैसे दें फीडबैक?: नागरिक फीडबैक के लिए ऑनलाइन पोर्टल cf.sbmurban.org तैयार किया गया है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर पूछे गए सवालों का जवाब भर सकते हैं और ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। एक फोन नंबर से एक ही फीडबैक दर्ज किया जा सकता है। केंद्रीय टीम द्वारा ऑन-फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान भी शहरवासियों से यही प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अंक स्वच्छ सर्वेक्षण के कुल स्कोर में जोड़े जाएंगे।

एयरपोर्ट पर युवती से छेड़छाड़ आरोपी को थाने लाया

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना एयरपोर्ट पर एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहां मौजूद भीड़ ने युवक को पड़कर एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया है। फिलहाल एयरपोर्ट थाने पर युवक से पूछताछ हो रही है। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने कैफिटेरिया में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की है। पुलिस के मुताबिक, लड़की की ओर से शिकायत लिखित रूप से नहीं की गई है। हालांकि, पुलिस मौखिक शिकायत के आधार पर ही घटना के बारे में पूछताछ के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मेंटल तौर पर युवक स्वस्थ नहीं लग रहा- पुलिस: एयरपोर्ट थानेदार सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि, 'घटना का सत्यापन किया जा रहा है। लड़के ने पूछताछ में बताया है कि छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। वह अंडरवियर नहीं पहनता है। पेंट उसकी कैसे फट गई।

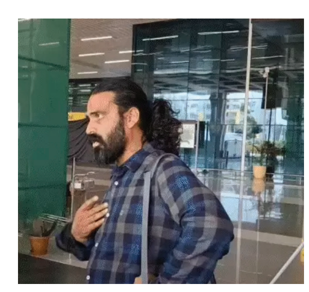

आसपास के लोगों से पूछताछ जारी

उसे पता नहीं चला। जानकारी होने के बाद वॉशरूम में चेंज करने गया था। इसी दौरान मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई।'

एयरपोर्ट थानेदार ने आगे कहा कि, 'फिलहाल सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद स्पष्ट तौर पर कुछ भी बताया जा सकता है। मेंटल तौर पर युवक स्वस्थ नहीं लग रहा है।'

पटना में लगेगा स्पोर्ट्स समर कैंप

, पटना

पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से स्पोर्ट्स समर कैंप की शुरूआत हुई है। बच्चों को खेल की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए 775 छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस समर कैंप में हर दिन दो सेशन होगा। पहला सेशन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और दूसरा सेशन शाम में 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा। जो लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, वे आज सुबह भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से होने वाले इस स्पोर्ट्स समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों को टीशर्ट, रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

फुटबॉल-बास्केटबॉल के साथ मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रन शंकरण ने कहा कि इस समर कैंप में बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग और अलग-अलग गेम के बारे में बच्चों

को जानकारी दी जाएगी। इस समय कैंप का मुख्य उद्देश्य गर्मी छुट्टी के समय बच्चों का ज्यादा समय मोबाइल और टीवी पर न बीते, बल्कि वह स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो जाए। इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, वार्मअप एक्सरसाइज, एथलेटिक्स, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, योगा, चेस, स्केटिंग, खो खो, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। एडवेंचरस स्पोर्ट्स के रूप में वॉल क्लाइंबिंग, सेल्फ डिफेंस के रूप में मार्शल आर्ट्स जैसे की ताइक्वांडो के बेसिक सिखाए जाएंगे।

कांग्रेस के 48 नए चेहरे सीख रहे राजनीति की भाषा

लोकतंत्र की शान, पटना

कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में चुने गए 48 लोगों को सदाकत आश्रम में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 38 प्रवक्ता, 5 रिसर्चर और 5 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल है। सभी प्रवक्ताओं को टाइम लिमिट का चैलेंज दिया जा रहा है, ताकि वह कम समय में अपनी बात रख सके। इसके अलावा रिसर्चर को डाटा सेंट्रिक ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस का ये टैलेंट हंट प्रोग्राम लगभग 2 महीने तक चला था। इसमें बिहार से 9100 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया था।

टाइम लिमिट का दिया जा रहा चैलेंज: कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रभूषण ने कहा कि, 'कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए सभी 48 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले विजुअल ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें सभी को एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा रहा है और उस पर बोलने को कहा जा रहा है। प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग में टाइम लिमिट का चैलेंज दिया जा रहा है, ताकि वह एक बाइट मोड

में कम समय में अपनी बात को रख सकें। सभी रिसर्चर को डाटा सेंट्रिक ट्रेनिंग दी जा रही है। ताकि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वह सही माध्यम से डाटा को कोट कर सकें। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या सोशल मीडिया वालों को यह टास्क दिया जा रहा है कि वह किस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि, 'यह ट्रेनिंग पूरे महीने चलेगी। इसके माध्यम से हम यह देखेंगे कि यह चुने गए कैंडिडेट कैमरा के सामने किस तरीके से बोल सकते हैं, उनका ओवरऑल नॉलेज कैसा है और कम समय में वह कितने इफेक्टिव तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। इस दौरान उन्हें करंट टॉपिक पर बहस करने को दिया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया जाएंगे। इस पहल के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज कर रही थी। पहला मीडिया प्रवक्ता-पैनलिस्ट जो टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक मंचों पर स्पष्टता, विश्वसनीयता और अनुशासन के साथ पार्टी का पक्ष रख सकें। दूसरा रिसर्च को-ऑर्डिनेटर ,जो तथ्य-आधारित, शोध-आधारित सामग्री, नीतिगत विश्लेषण और मुद्दा-ब्रीफ तैयार कर पार्टी के संदेश को मजबूती दें। तीसरा पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप नेटवर्क, स्थानीय मीडिया और ज़मीनी स्तर पर पार्टी का संदेश व्यापक रूप से पहुंचाए।

♦ पटना सदाकत आश्रम में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग, कैमरे के सामने बोलने का अभ्यास जारी

संक्षिप्त समाचार

पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने अंधे कत्ल का किया खुलासा

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। थाना बहरी अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में सडक़ के किनारे एक अज्ञात महिला के अधजले शव के मामले का आज पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 6 जून 2026 को थाना बहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में सडक़ किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना बहरी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल से जले-अधजले कपड़ों के टुकड़े, धागे के खोखे, जूट के बोरे के अवशेष एवं अन्य महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य बरामद किए गए।

बढ़ौरा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। अधिमास के चौथे सोमवार को क्षेत्र के प्रसिद्ध बढ़ौरा शिव मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मिली जानकारी के मुताबिक इस समय सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था और दिनभर भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। सीधी जिले के अलावा आसपास के जिलों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। सेमरिया थाना सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या चोरी की आशंका को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी गई। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए मंदिर से पहले ही चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था और वाहनों को निर्धारित स्थानों पर पार्क कराया गया। मंदिर परिसर के आसपास लगी नारियल, चुनरी, प्रसाद एवं पूजन सामग्री की दुकानों पर भी दिनभर अच्छी खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं की खरीदारी से स्थानीय व्यापारियों में उत्साह देखने को मिला। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया।

औजल्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा परिचय एवं संवाद सत्र का आयोजन

लोकतंत्र की शान : राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट , दिनांक 7 जून, रविवार को के-3 जी रियलिटी कार्यालय, अल्फा सिटी में ट्रस्ट की ओर से एक परिचय एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फैमिली के सदस्यों के साथ-साथ उत्तराखंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (UPES), देहरादून के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता की। ये विद्यार्थी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं तथा अपनी दो माह की इंटर्नशिप के अंतर्गत संस्था से जुड़े हैं। कार्यक्रम के दौरान आगामी दो महीनों में आयोजित किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा समाजहित में किए जा सकने वाले कार्यों एवं उनकी सहभागिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत जून एवं जुलाई माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई तथा विभिन्न सामाजिक अभियानों एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य श्रीमती गुंजन भटनागर, श्री संजय भटनागर, श्रीमती दिव्या सिंगला, श्री ध्रुव सिंगला, श्रीमती दीपिका गुप्ता, श्रीमती गीता, श्री शुभम, श्रीमती सतीश कुमारी, श्रीमती शैलजा गुप्ता, श्री मनीष कुमार, श्री एन. डी. गोयल एवं श्रीमती कविता चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना तथा समाज के विभिन्न वर्गों के हित में प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना रहा

अमृतसर डीसीपी कार्यालय की असलहा शाखा में आकस्मिक फायरिंग, एएसआई घायल

लोकतंत्र की शान : अमृतसर। अमृतसर में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय की असलहा शाखा में सोमवार को आकस्मिक फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। यह घटना उस समय हुई, जब एक लाइसेंसी हथियार की जांच के दौरान अचानक .30 बोर की पिस्तौल से गोली चल गई।पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 11 बजे एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार की जांच करवाने के लिए असलहा शाखा पहुंचा था। जांच प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी पर तैनात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) नारायण दास पिस्तौल की जांच कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हथियार से गोली चल गई और एएसआई नारायण दास को जा लगी, जिससे वह घायल हो गए।घटना के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल एएसआई को तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।पुलिस सूत्रों का कहना है कि असलहा शाखा में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है।

जिला कलक्टर ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दी सख्त समयसीमा की चेतावनी

» बजट घोषणाओं और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। नागौर जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों तथा जन शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति पर विभागवार चर्चा की गई तथा कार्यों में गति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने सभी स्वीकृत विकास कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

बजट घोषणाओं और आधारभूत ढांचे के कार्यों की समीक्षा-जिला कलक्टर ने विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए रेलवे अंडरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और सड़क निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आमजन की सुविधाओं से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत जिला विकास वार्षिक योजना 2026-27 के क्रियान्वयन, धनराशि के उपयोग, परिसंपत्तियों के सृजन और गुणवत्ता नियंत्रण की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

विकास निधियों और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर फोकस-बैठक में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा एडीपीसी के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नगर परिषद और विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा संचालित आधारभूत सुविधाओं के कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए।

जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर सख्ती-जिला कलक्टर ने सीएमआईएस पोर्टल, संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लंबित प्रकरणों तथा सीपीग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जन शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो।

पंच गौरव और प्रमुख अभियानों की समीक्षा-बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे कार्यों, स्वीकृत परियोजनाओं और व्यय की गई राशि की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने सभी कार्यों को तय मानकों के अनुसार और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अधिकाधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं, अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

"जनहित सर्वोपरि" की भावना से कार्य करने के निर्देश-अंत में जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

मजदूरो से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 5 घायल, 2 गंभीर

» रामपुर नैकिन थाना के कोदईडाड़ गांव में भीषण सडक़ हादसा

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के रामपुर नैकिन थानांतर्गत कोदईडाड़ गांव में सोमवार दोपहर मजदूरों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली बेकाबू होकर सडक़ किनारे पलट गई। इस हादसे में पांच मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से दो की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रैक्टर-ट्रॉली बिजली के टावर बनाने के काम में लगे मजदूरों को लेकर चुरहट की तरफ जा रही थी। दोपहर करीब 3 बजे कोदईडाड़ के पास एक मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत तेज थी, इसी वजह से यह हादसा इतना बड़ा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही 108 एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को रामपुर नैकिन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 108 एंबुलेंस के ईएमटी रवि शुक्ला ने बताया कि कुल पांच गंभीर रूप से जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में शामिल शिव प्रसाद रावत और आशा रावत के सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया है। इसके अलावा मुन्ना, रामनाथ और सानू रावत भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज रामपुर नैकिन अस्पताल में ही चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जिनमें से कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस पूरे हादसे के बाद एक हैरान करने वाली बात सामने आई। ट्रैक्टर का ड्राइवर पलटे हुए वाहन को सीधा करने में कामयाब रहा और इसके बाद वह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आधी रात पूर्व मंत्री इंद्रजीत की लगा दी प्रतिमा

» अनुमति न मिलने को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट
» सीधी की सियासत में आया नया उबाल

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने बीती देर रात समर्थकों द्वारा पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई। यह खबर फैलते ही सियासत गरमा गई। दरअसल प्रतिमा स्थापना की जानकारी मिलते ही रात में ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट हो गया। रात में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिमा स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। समर्थकों द्वारा प्रतिमा स्थापना के लिए बड़ी क्रेन का उपयोग किया गया था। जिससे भारी-भरकम प्रतिमा को पूर्व में बनाए गए प्रतिमा स्थल पर स्थापित किया जा सके। प्रतिमा स्थापना के बाद समार्थकों का कहना था कि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं सात बार सीधी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा स्थापना की मांग लंबे अरसे से हो रही थी। प्रतिमा स्थापना के लिए वर्ष 2023 में नगर पालिका परिषद सीधी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नपा की बैठक में प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हालांकि इसके अनावरण और स्थापना की अनुमति के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास किए गए लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। समर्थकों का कहना है कि वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद भी जब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तब स्थानीय नागरिकों और पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार के समर्थकों ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा को प्रस्तावित स्थल पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। सोमवार सुबह प्रतिमा स्थापना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे और इसे जिले के लोकप्रिय नेता को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। वहीं प्रतिमा स्थापना की इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े किए हैं। विरोध के स्वर सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

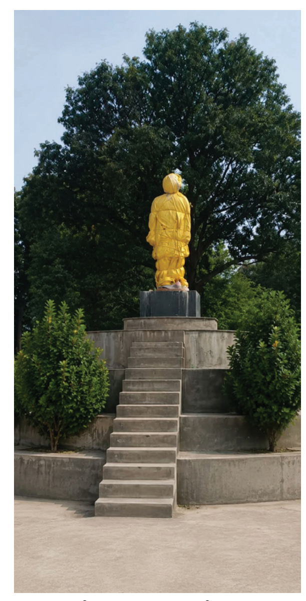

नगर पालिका बनने के तीन वर्ष बाद भी मेड़ता रोड विकास से वंचित

» गंदे नाले, टूटी सड़कें और जल निकासी की बदहाल व्यवस्था से जनता बेहाल

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड (नागौर), एजाज़ अहमद उस्मानी। ग्राम पंचायत से क्रमोन्नत होकर नगर पालिका बने लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद मेड़ता रोड कस्बे में विकास कार्यों की स्थिति बेहद निराशाजनक बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका बनने के बाद जिस तेज विकास की उम्मीद थी, वह आज तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। कस्बे की स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास के नाम पर मेड़ता रोड अब भी पिछड़ेपन की तस्वीर पेश कर रहा है। कस्बे के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। न तो नियमित रूप से साफ-सफाई व्यवस्था सुचारू है और न ही जल निकासी की कोई प्रभावी प्रणाली दिखाई देती है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जब सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है और कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं।

मुख्य मार्गों पर गंदगी और जर्जर नाले-कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, मेड़ता सिटी मार्ग, नागौर सड़क मार्ग सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नाले टूटे पड़े हैं। इन नालों से लगातार गंदा पानी बहकर सड़कों पर फैलता रहता है, जिससे न केवल दुर्गंध का माहौल बनता है बल्कि संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई जगहों पर नाले खुले पड़े हुए हैं, जो राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय या कम रोशनी में इन खुले नालों में गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा है।

बाइपुरा क्षेत्र की हालत सबसे खराब-कस्बे के बाइपुरा क्षेत्र की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई जा रही है। यहां न तो गंदे पानी की उचित निकासी व्यवस्था है और न ही सड़कें ठीक हालत में हैं। जगह-जगह गड्ढों और कीचड़ के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हल्की बारिश में ही सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। कई बार शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

सड़क किनारे अधूरी नाली, गंदा पानी जमा | कीचड़ से लथपथ गली, आवागमन हुआ मुश्किल | नाल पर टूटी पड़ी पट्टियां | जलभराव से बनी तालाब जैसी स्थिति | सड़क पर कीचड़ और जलभराव, लोग परेशान

नशीली सिरप के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट के मार्गदर्शन में थाना अमिलिया पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की गई है। पुलिस के अनुसार दिनांक 7 जून 2026 को थाना अमिलिया पुलिस की टीम अपराध विवेचना एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम कोदौरा में मौजूद थी। इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कोडीन फॉस्फेट युक्त ऑनरेक्स कफ सिरप लेकर हनुमना की ओर से हिनौती आ रहा है। सूचना की तस्दीक करते हुए पुलिस टीम द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ग्राम हरदी स्थित मुड़ा पहाड़ शिव मंदिर के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति विक्रांता मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे बैग से 26 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप प्रत्येक 100 एमएल बरामद हुई, जिसमें कोडीन फॉस्फेट पाया गया। आरोपी से उक्त मादक पदार्थ के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

कलेक्टर के निर्देश पर स्थापित हुआ 'बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष' कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनीः मानसून के आगमन के पूर्व ही जिले में संभावित बाढ़ और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर 15 जून से कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक-99 में 'जिला स्तरीय बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष' कार्य करना शुरू कर देगा।। यह नियंत्रण कक्ष 24x7 संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07622-220070 और 07622-220071 है। कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाढ़ नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती विंकी सिंघमारे को नोडल अधिकारी और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के जिला प्रबंधक श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की तैनाती तीन पालियों में की गई है।

पुष्कर में 2 करोड़ की लागत से मातृ-शिशु अस्पताल बनेगा

» संत पांचाराम महाराज ने की घोषणा
» खेजड़ा आश्रम के संत हैं पांचाराम जी महाराज

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़ता के निकटवर्ती दरियाव खेजड़ा आश्रम के संत पांचाराम महाराज ने तीर्थनगरी पुष्कर में महिलाओं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल निर्माण की घोषणा की है। यह घोषणा वाडभी गांव के रामसभा भवन उद्घाटन समारोह के दौरान की गई, जिसे ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संत पांचाराम महाराज लंबे समय से "मानव सेवा ही माधव सेवा" के सिद्धांत को जीवन में उतारते हुए जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब तक वे विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य परियोजनाओं में लगभग 15 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग दे चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ-प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण के बाद पुष्कर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। खासकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में प्राथमिक और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी मजबूत होगी।

पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं में दिया योगदान-संत पांचाराम महाराज इससे पहले भी प्रदेश के कई अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में सहयोग दे चुके हैं। उनके योगदान से मेड़ता सिटी के राजकीय अस्पताल को 3.71 करोड़ रुपए, नागौर और सोजत के अस्पतालों को 2.50-2.50 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। इसके अलावा डाडमी, रेण और मूंडवा सहित कई क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य और जनसुविधाओं के विकास कार्यों में उनका योगदान रहा है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल पीएम नहीं आये संसद में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम

काठमांडू। आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं होंगे। इसके नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और विपक्षी दलों के बीच सोमवार को हुई वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक में शामिल नेताओं के अनुसार लामिछाने ने विपक्षी दलों को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नेपाल की सीमा संबंधी विवादित टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देने के लिए सदन में नहीं आएंगे। इसके बजाय उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे स्वयं और विदेश मंत्री शिशिर खनाल के संसद में उपस्थित होकर विपक्ष की चिंताओं का जवाब दे सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस बयान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, उस पर स्पष्टीकरण केवल प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। सीपीएन-यूएमएल के मुख्य सचेतक ऐन बहादुर महर ने कहा कि विपक्षी दलों ने बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री स्वयं संसद में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते, तब तक सदन का अवरोध जारी रहेगा। दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर कायम रहने के कारण सर्वदलीय बैठक बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई और संसदीय गतिरोध बरकरार रहा। विपक्षी दलों ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री के सदन में आकर जवाब देने तक वे संसद की कार्यवाही बाधित करते रहेंगे। सत्तारूढ़ पक्ष ने संकेत दिया है कि सरकार इस विवाद पर जवाब देने के लिए रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने और विदेश मंत्री शिशिर खनाल पर निर्भर रहेगी।

भारत से लौटे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल अगले सप्ताह चीन दौरे पर जाएंगे

काठमांडू। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल अगले सप्ताह चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। भारत दौरे से लौटने के बाद उनका चीन भ्रमण तय किया गया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री खनाल 14 जून को चीन के लिए रवाना होंगे। 15 और 16 जून को उनके औपचारिक कार्यक्रम निर्धारित हैं। इस दौरान उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख लियू हैशिंग से मुलाकात होने की योजना है। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री खनाल बीजिंग में नेपाली प्रवासी समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। उनका 17 जून को नेपाल लौटने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री के चीन दौरे की तिथि और एजेंडा को लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक घोषणा १२ जून को की जाएगी । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ने कहा कि विदेश मंत्री के भारत यात्रा पर अधिक ध्यान केंद्रित रहने के कारण चीन दौरे की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने बताया, "हम चीनी मित्रों के साथ लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही कोई नया विकास होगा, हम औपचारिक जानकारी साझा करेंगे।" विदेश मंत्री खनाल 5 जून को भारत यात्रा पर गए थे और 7 जून को काठमांडू लौटे। भारत प्रवास के दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले सहित कई नेताओं से मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दस साल पूरे, देशभर में मंगलवार से शुरू होंगे विशेष कार्यक्रम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 9 जून से देशभर में विशेष समारोह और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि "पीएमएसएमए के 10 साल-देखभाल के एक दशक" थीम के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के तहत उपलब्ध नौ निःशुल्क एवं सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना और समय पर प्रसवपूर्व जांच के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह सम्मान सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के एक दशक के योगदान को समर्पित होगा। उल्लेखनीय है कि इस अभियान की शुरुआत 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले 10 वर्षों में यह अभियान मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरा है। इस योजना से प्रसवपूर्व जांच, जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

खराब मौसम के कारण पुरी में उतारना पड़ा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का हेलीकॉप्टर

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के हेलीकॉप्टर को सोमवार को खराब मौसम के चलते पुरी में एहतियातन उतारना पड़ा। प्रतिकूल मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का भुवनेश्वर में निर्धारित लैंडिंग करना संभव नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री माझी मयूरभंज जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भुवनेश्वर लौट रहे थे। इसी दौरान भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब होने से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलीकॉप्टर को पुरी की ओर मोड़ दिया गया, जहां इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर ने पुरी के समंगा अस्थायी बस स्टैंड परिसर में सुरक्षित रूप से उतरान भरी। अचानक हुई इस लैंडिंग के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। अधिकारियों ने बताया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय पूरी तरह एहतियातन लिया गया था। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री की आगे की यात्रा को लेकर समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी थी।

नॉर्वे शतरंज चैंपियन प्रज्ञानानंद का सम्मान, मुख्यमंत्री ने खेली शतरंज की बाजी

चेन्नई। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज-2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने के बाद सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण शतरंज मुकाबला भी खेला गया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। चेन्नई सचिवालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान प्रज्ञानानंद ने अपनी विजेता ट्रॉफी मुख्यमंत्री को दिखाई। मुख्यमंत्री विजय ने उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता ने भारत और तमिलनाडु का गौरव बढ़ाया है। राज्य सरकार की ओर से उन्हें 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और स्मृति चिह्न भेंट किया गया। मुलाकात का सबसे रोचक क्षण तब आया, जब मुख्यमंत्री विजय ने स्वयं शतरंज बोर्ड मंगवाकर प्रज्ञानानंद के साथ एक मैत्रीपूर्ण मुकाबला खेला। आमतौर पर किसी विश्वस्तरीय ग्रैंडमास्टर के सामने सामान्य खिलाड़ी कुछ ही मिनटों में हार मान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने लगभग 15 मिनट तक मुकाबला किया। अंततः प्रज्ञानानंद ने उन्हें चेकमेट देकर जीत दर्ज की। इस मुकाबले का वीडियो सामने आने के बाद लोग मुख्यमंत्री की शतरंज समझ और खेल कौशल की भी सराहना कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, प्रज्ञानानंद को राज्य की "एलाइट" योजना के तहत प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये की विशेष सहायता भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार शतरंज के विकास और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है।

मुंबई में बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक की मौत

एजेंसी, मुंबई

♦ कंडक्टर समेत 3 घायल, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया

मुंबई में सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे दादर के प्लाजा सिनेमा के पास एक BEST (नगर निकाय) बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 22 साल के एक लड़के की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में बस का कंडक्टर भी शामिल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मोड़ पर ट्रैफिक धीमा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस गाड़ियों को रौंदते हुए निकल गई। बस की टक्कर के बाद तेज आवाज आई और सड़क पर गाड़ियों का मलबा बिखर गया। शिवाजी पार्क पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने वहां पहुंचकर गाड़ी में फंसे घायलों को रेस्क्यू कर निकाला। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

मुंबई के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचलाः मुंबई के भांडुप में रेलवे स्टेशन के बाहर 29 दिसंबर 2025 को देर रात एक बस ने 13 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि हादसा रात 9:35 बजे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बस से हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, BEST की बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे लोगों को चपेट में ले लिया।। हादसे के बाद बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद एम्बुलेंस, मुंबई फायर ब्रिगेड और BEST की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ितों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से राजावाड़ी और एम.टी. अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। बस ने एक बिजली के खंभे को भी टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसाः महाराष्ट्र के ठाणे में 13 अप्रैल को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दो गंभीर घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10:45 बजे मुर्बाड के गोविली गांव स्थित रैता ब्रिज पर हुआ। कल्याण से मुर्बाड जा रही वैन की सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं, अन्य दो लोग घायल हैं, जिन्हें उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान जारी है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पीडिया के जंगल से 3 आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद

एजेंसी, बीजापुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर हर्रा/अर्रा (पीडिया) गांव के जंगल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सोमवार को 3 आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद किए गए।

यह कार्रवाई कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन में की गई। बरामद डंप से गन पाउडर, जिलेटिन स्टिक, कमर्शियल डेटोनेटर और मेडिकल सामग्री सहित कुल 21 प्रकार के नक्सल सामग्री बरामद किए गए, जिन्हें नक्सलियों ने छिपाकर रखा था।

गोपनीय सूचना के आधार पर कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं द्वितीय कमान अधिकारी कुमार नीरज की देख-रेख में एफ/199 कंपनी ने हर्रा/अर्रा (पीडिया) गांव के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कंपनी कमांडर केबी. पांडा के नेतृत्व में जवानों ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी कर चरणबद्ध सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अभियान के दौरान नक्सलियों के छिपाकर रखे गए 3 आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद किए गए। तलाशी में मिले डंप से आईईडी निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे गन पाउडर, जिलेटिन स्टिक, कमर्शियल डेटोनेटर के साथ 15 मेडिकल सामग्री सहित कुल 21 प्रकार की नक्सल सामग्री जब्त की गई। सुरक्षाबलों के अनुसार हर्रा/अर्रा और आस-पास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन लगातार चल रहे अभियानों के चलते अब यहां नक्सल प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। बल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की सुरक्षा, शांति और विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल में ईडी ने की छापेमारी

एजेंसी, नई दिल्ली

♦ 142 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में चार जगह पर छापेमारी की। जांच में अब तक 142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का पता चला है। मामला म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से संबंधित है। ईडी के आइजोल उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत यह कार्रवाई की। यह जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की अगरतला जोनल यूनिट द्वारा दर्ज मामले पर आधारित है। इस मामले में 21 अगस्त 2025 को त्रिपुरा में 49.101 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। ईडी के अनुसार, जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है, जो म्यांमार से मिजोरम के चम्फाई-जोखावथार क्षेत्र के रास्ते मेथामफेटामिन भारत लाता था। इसके बाद खेप को त्रिपुरा में मौजूद रिसीवरों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि तस्करी से अर्जित धन को कई बैंक खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर छिपाया और स्थानांतरित किया गया।

मौसम की सटीक और समय से जानकारी मिलने से जन व धन हानि बचाना हुआ संभवः मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, लखनऊ

♦ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम केंद्र का किया शुभारंभ
♦ पिछले 12 सालों में मौसम विभाग के 136 से अधिक स्थापित हुए रडारः केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम को सटीक व विश्वसनीय जानकारी मिलने से न केवल जन धन हानि को बचाया जा सकता है बल्कि कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम विभाग सटीक और विश्वसनीय जानकारी दे रहा है और इससे आम लोगों को लाभ भी हो रहा है। उप्र सरकार इसे सेटेलाइन के माध्यम और बेहतर बनाने के लिए हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजधानी लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में मौसम विज्ञान के लखनऊ केन्द्र को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र में परिवर्तित करने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट से शुभारंभ किया। इस मौके केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह व मौसम विभाग के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी ने प्राचीन काल में मौसम और जलवायु की गणना और अनुमान का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय ऋषि और मनीषी पंचाग से सही गणना करते थे। कई लोक कहावतों और परंपराओं से भी मौसम के बारे में सही सही जानकारी मिलती थी लेकिन अब तकनीकी युग में हमें और बेहतर जानकारियों की जरूरत होती है और पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर आजादी के बाद से ही यह काम हुआ होता तो आज किसानों को खेती में अच्छी पैदावार मिलती और प्राकृतिक आपदों में जन धन की हानि भी कम होती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक वर्षा का आकलन करने के लिए उपकरण लगाए हैं ताकि फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन किसानों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय मौसम विभाग बहुत तेजी से सटीक और विश्वसनीय आंकडे दे रहा है। उन्होंने हाल ही में शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में आयी बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि घटना से पहले मौसम विभाग का अलर्ट आने पर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया जबकि दो महिलाएं मना करने के बावजूद जल की ओर गयीं और उनकी मौत हो गयी।

ट्राई ने मेघालय और पंजाब में जांची मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च में मेघालय और अप्रैल में पंजाब में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच की। मेघालय के ईस्ट और वेस्ट जयंतिया हिल्स जिलों तथा एनएच-6 पर रथा चेरे खसिया पुंजी से जोवाई तक और पंजाब के चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला शहरी क्षेत्र में की गई जांच में जियो और एयरटेल ने औसतन सबसे तेज डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जबकि बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया में कवरेज गैप और कॉल ड्रॉप की समस्या अधिक रही। ट्राई के अनुसार मेघालय मार्च महीने में 213 किलोमीटर सिटी ड्राइव और 98.9 किलोमीटर हाईवे ड्राइव के दौरान नेटवर्क की स्थिति का परीक्षण किया गया। यहां कवरेज गैप और कॉल ड्रॉप की समस्या प्रमुख रही। हाईवे ड्राइव में वोडाफोन-आइडिया के 12,887 सैंपल में से 4,946 में सिग्नल कमजोर पाया गया, जबकि बीएसएनएल के 8,972 सैंपल में से 2,719 में कवरेज की कमी रही। औसत डाउनलोड स्पीड एयरटेल की 72.24 से 88.50 एमबीपीएस, जियो की 97.89 से 122.77 एमबीपीएस, बीएसएनएल की 9.54 से 4.37 एमबीपीएस और वोडाफोन-आइडिया की 25.45 से 23.35 एमबीपीएस रही। अपलोड स्पीड में एयरटेल ने 14.50 से 20.22 एमबीपीएस और जियो ने 6.21 से 5.64 एमबीपीएस दर्ज की, जबकि बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। कॉल ड्रॉप दर में बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया सबसे पीछे रहे, जहां क्रमशः 34 और 30 कॉल ड्रॉप दर्ज हुईं।

पंजाब में अप्रैल के दौरान 453.2 किलोमीटर सिटी ड्राइव, 15 हॉटस्पॉट और 1.5 किलोमीटर वॉक टेस्ट किया गया। इसमें एयरटेल और जियो ने क्रमशः 169.66 एमबीपीएस और 203.16 एमबीपीएस औसत डाउनलोड स्पीड दर्ज की। वोडाफोन-आइडिया की स्पीड 48.27 एमबीपीएस और बीएसएनएल की मात्र 11 एमबीपीएस रही। अपलोड स्पीड में एयरटेल 23.28 एमबीपीएस, जियो 23.85 एमबीपीएस, वोडाफोन-आइडिया 17.97 एमबीपीएस और बीएसएनएल 4.96 एमबीपीएस पर रहा। कॉल ड्रॉप दर में एयरटेल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जहां एक भी कॉल ड्रॉप दर्ज नहीं हुई, जबकि बीएसएनएल में 24 कॉल ड्रॉप दर्ज की गईं। कॉल साइलेंस इंस्टेंस में भी एयरटेल और जियो का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

मेघालय में एयरटेल में सिटी ड्राइव के दौरान 27 बार और हाईवे ड्राइव में 8 बार कॉल साइलेंस (कॉल के दौरान आवाज चली जाना) दर्ज हुआ। जियो में क्रमशः 18 और 6 बार, जबकि बीएसएनएल में 10 और 9 बार तथा वोडाफोन-आइडिया में 3 और 2 बार कॉल साइलेंस इंस्टेंस पाए गए। अपलोड स्पीड में एयरटेल ने शहरों में 14.50 एमबीपीएस और हाईवे में 20.22 एमबीपीएस की स्पीड दर्ज की।

असम मंत्रिमंडल के विभागों का आवंटन, मुख्यमंत्री के पास गृह, लोक निर्माण, ऊर्जा

एजेंसी, गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया। हाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को उनके-उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा अपने पास गृह एवं राजनीतिक, लोक निर्माण (भवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क), ऊर्जा तथा जनसंपर्क विभाग रखेंगे। जयंत मल्लबरुवा को वित्त, पर्यावरण एवं वन तथा खान एवं खनिज विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, केशव महंत को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन तथा सामान्य प्रशासन विभाग सौंपे गए हैं।

अशोक सिंघल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का दायित्व दिया गया है। पीयूष हजारिका कृषि, सिंचाई एवं संसदीय कार्य विभाग संभालेंगे, जबकि डॉ. रणोज पेगु विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, जनजातीय कार्य (मैदानी क्षेत्र) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व करेंगे। अश्विनी राय सरकार को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, भूमि संरक्षण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिए गए हैं। बिमल बोरा को सांस्कृतिक कार्य, उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उपक्रम तथा एक्ट ईस्ट नीति विभाग सौंपा गया है। विश्वजीत दैमारी को हथकरघा, वस्त्र एवं रेशम उद्योग, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, स्वदेशी एवं जनजातीय आस्था एवं संस्कृति तथा खेल विभागों की जिम्मेदारी मिली है।

गुजरात से राज्यसभा के लिए भाजपा के चार उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

एजेंसी, गांधीनगर

गुजरात से राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया के तहत गुजरात की चार रिक्त सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार उम्मीदवारों राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कणजारिया ने सोमवार को गुजरात विधानसभा स्थित रिटार्निंग आफिस में विजय मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गुजरात की 11 राज्यसभा सीटों में से रिक्त हुई 4 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा द्वारा घोषित सभी चार उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। विधानसभा में भाजपा के मजबूत संख्याबल को देखते हुए चारों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर, विधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो चारों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। इसके साथ ही गुजरात के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनेगी जब राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं होगा।

टीएमसी में टूट की अटकलें तेज, भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे सुखेंदु शेखर सहित 14 सांसद

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) टूटती नजर आ रही है। पहले टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बनाया और अब यह टूट संसदीय दल तक पहुंच गई है। टूट की अटकलों के बीच सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के करीब 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के घर पहुंचे और बंद कमरे में बैठक की। बैठक में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर भी शामिल हुए। सुखेंदु ने आज ही राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देब भी मौजूद रहे। इस राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले सुखेंदु शेखर ने मीडिया से बातचीत में आरजी कर अस्पताल मामले में तृणमूल कांग्रेस के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने राय रखी थी। तब से पार्टी के भीतर उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। सुखेंदु ने कहा कि उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की थी क्योंकि मेरा मानना था कि सबूतों को नष्ट करने में उनकी अहम भूमिका थी। इसके कारण उन्हें पार्टी से अलग थलग कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि संसद में दलबदल विरोधी कानून को दरकिनार करने के लिए बागी गुट को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के पास वर्तमान में लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं।

पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष औऱ विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कुछ संगठनात्मक फेरबदल किए। चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सुब्रता बख्शी की जगह ली है। खास बात यह है कि बैठक में बागी खेमे से कोई भी उपस्थित नहीं था। बैठक में मदन मित्रा, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, अशोक देब, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अभिषेक बनर्जी जैसे पुराने नेता ही मौजूद थे।

ईरान-इजराइल संघर्ष विराम का टूटनाः तेल कीमतों में उछाल, व्यापारिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय अस्थिरता और महायुद्ध की आशंकाएं, विश्व शांति,मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा

लोकतंत्र की शान

» ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य टकराव विश्व शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था,ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है

» विश्व शांति की रक्षा,आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा और मानवता के हित में युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग सिद्ध हो सकती है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर मध्य पूर्व एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां किसी भी छोटी चिंगारी से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़क सकती है। अप्रैल 2026 से लागू अस्थायी संघर्ष विराम (सीजफायर) के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बना हुआ था,किंतु 8 जून 2026 को दोनों देशों के बीचप्रत्यक्ष मिसाइल और हवाई हमलों ने यह संकेत दे दिया कि संघर्ष विराम गंभीर संकट में पड़ गया है।विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जबकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है और दुनिया को एक बार फिर बड़े युद्ध की आशंका सताने लगी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव भर नहीं है,बल्कि इसके पीछे भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा,क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई,सुरक्षा चिंताएं,परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अविश्वास और अनेक प्रॉक्सी संगठनों की भूमिका भी जुड़ी हुई है।पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष लगातार बढ़ते रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया और इराक में विभिन्न सशस्त्र गुट तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की राजनीति ने इस पूरे संकट को और अधिक जटिल बना दिया है। साथियों, मीडिया में अनुसार 8 जून 2026 को सामने आई घटनाओं के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस को लक्ष्य बनाकर मिसाइल हमले किए। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइली हमलों के जवाब में की गई। दूसरी ओर इजराइली सेना ने ईरान के पश्चिमी और मध्य भागों में स्थित रडार केंद्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा अन्य रणनीतिक ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम की व्याख्या दोनों पक्ष अलग-अलग तरीके से कर रहे थे। ईरान का आरोप है कि लेबनान पर इजराइली हमले सीजफायर की भावना के विरुद्ध थे,जबकि इजराइल का तर्क है कि उसकी सैन्य कार्रवाई उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसी मतभेद ने अंततः स्थिति को फिर से युद्ध की दिशा में धकेल दिया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह संकट अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं तथा लाल सागर में इजराइली समुद्री गतिविधियों को बाधित करने की चेतावनी दी है। यदि लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। साथियों अमेरिका इस पूरे संकट में अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों से संयम बरतने और तत्काल संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री से बातचीत कर आगे सैन्य कार्रवाई को सीमित रखने का आग्रह किया। अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि यह संघर्ष पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलता है तो अमेरिका स्वयं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उलझ सकता है। वास्तव में यह संकट ऐसे समय में उभरा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, व्यापारिक तनाव, मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता ने पहले ही विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है।ऐसे में मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की संभावना निवेशकों, व्यापारिक संस्थानों और सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। साथियों, तेल बाजार इस तनाव का सबसे पहला और सबसे संवेदनशील शिकार बनता दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों की ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष बढ़ने की खबरों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो तेल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं।तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ती है, उत्पादन महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। विकासशील देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि वे ऊर्जाआयात पर अधिक निर्भर रहते हैं।भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है। साथियों,भारत की दृष्टि से यह संकट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर भारत के ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों भारतीय नागरिक मध्य पूर्व में कार्यरत हैं। यदि क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा यात्रा संबंधी सलाह जारी करना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकता है। इससे न केवल सैन्य संघर्ष बढ़ेगा बल्कि मानवीय संकट भी गहरा सकता है। लाखों लोगों के विस्थापन, शरणार्थी संकट और बुनियादी ढांचे की तबाही जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

साथियों, इतिहास गवाह है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। मिसाइलें और बम केवल सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बल्कि शहरों, अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही उच्च तकनीक वाले हथियारों से लैस हैं। इसलिए यदि युद्ध व्यापक रूप लेता है तो इसका मानवीय नुकसान अत्यंत गंभीर हो सकता है।संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों, एशियाई शक्तियों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे दोनों पक्षों को संवाद की मेज पर वापस लाएं। कूटनीति, मध्यस्थता और विश्वास निर्माण के उपाय ही इस संकट का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। साथियों, विश्व राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में यह भी स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा क्षेत्रीय युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह जाता। वैश्विक वित्तीय बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव केवल मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है।वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तत्काल और प्रभावी संघर्ष विराम की है। दोनों देशों को यह समझना होगा कि सैन्य टकराव की निरंतरता किसी पक्ष को स्थायी विजय नहीं दे सकती, लेकिन पूरे क्षेत्र को अस्थिर अवश्य कर सकती है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य प्रभावशाली देशों को मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जो न केवल युद्ध रोक सके बल्कि भविष्य में ऐसे संघर्षों को दोबारा भड़कने से भी रोक सके। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि 8 जून 2026 की घटनाओं ने यह संकेत दे दिया है कि मध्य पूर्व की शांति अभी भी अत्यंत नाजुक स्थिति में है।ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य टकराव विश्व शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तेल कीमतों में उछाल, व्यापारिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय अस्थिरता और महायुद्ध की आशंकाएं इस संकट को और अधिक संवेदनशील बना रही हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि दोनों देशों को संयम, संवाद और स्थायी शांति की दिशा में प्रेरित किया जाए। विश्व शांति की रक्षा, आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा और मानवता के हित में युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति ही सबसे प्रभावी मार्ग सिद्ध हो सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक - क्र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

आशियाना और उपजाऊ जमीन गंवा देने का एक अंतहीन सिलसिला

लेखक- कुमार कृष्णन

गंगा नदी का कटाव एक विकराल समस्या है, जो हर साल सैकड़ों किसानों और परिवारों को बेघर कर रही है। बिहार के मुंगेर, खगड़िया, बेगुसराय के साथ साथ की जिलों में यह समस्या है।हर साल गंगा का बढ़ता कटाव किसानों की जमीन निगल रहा है, घरों पर संकट खड़ा कर रहा है और हजारों परिवारों का भविष्य असुरक्षित बना रहा है। गंगा कटाव पीड़ितों का दर्द केवल बाढ़ के समय का नहीं, बल्कि हर साल अपना आशियाना और उपजाऊ जमीन गंवा देने का एक अंतहीन सिलसिला जारी है।हर साल कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि और लोगों के पक्के घर गंगा में समा जाते हैं।पीड़ित परिवारों का दर्द अकल्पनीय और गहरा होता है। अपनी मेहनत की कमाई से बनाया गया आशियाना और पुस्तैनी जमीन जब पल भर में नदी के गर्भ में समा जाती है, तो वे पूरी तरह बेघर और भूमिहीन हो जाते हैं। पीड़ित परिवारों के पास न तो घर बचता है और न ही खेती के लिए एक इंच जमीन। वे पूरी तरह से बेघर हो जाते हैं।तक़रीबन 18 साल से कटाव पीड़ित अपने अस्तित्व की रक्षा, खेती बचाने और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।टीकारामपुर, दक्षिणी रहीमपुर, मध्य रहीमपुर, उत्तरी रहीमपुर और बरारी रघुनाथपुर समेत कई पंचायतों में गंगा का कटाव लगातार बढ़ रहा है। इससे खेती योग्य जमीन तेजी से नदी में समा रही है और कई परिवारों के सामने विस्थापन का खतरा खड़ा हो गया है। समाजसेवी नागेंद्र सिंह त्यागी , राकेश कुमार मंडल और ई. धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि गंगा कटाव अब विकराल रूप धारण कर चुका है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हजारों परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विकास का एक अलग ही माडल चल पड़ा है। गंगा के किनारे मरीन ड्राइव की बात तो की जाती है, लेकिन गंगा के कटाव और विस्थापन का सवाल हाशिए पर है। तभी तो 18 साल से लगानी लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र यानी दियारे की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है। कटाव पीड़ितों ने अपनी पीड़ा का इजहार गंगा किनारे उपवास कर रखा और गंगा मैया से मुक्ति की गुहार लगाई।

मुंगेर सदर प्रखंड के टीकारामपुर में गंगा कटाव के स्थायी समाधान हेतु हो रहे जन आंदोलन के दूसरे चरण में गंगा पूजन एवं एकदिवसीय उपवास किया गया। आंदोलन से आरंभिक दौर से जुटे अनिल यादव बताते हैं कि गंगा कटाव रोकने हेतु बंडाल के सवाल पर 2008 से हीं आंदोलन का शुरुआत किया था। जो श्याम किशोर यादव, शिवनंदन यादव, जनार्दन यादव, इंद्रदेव यादव जैसे प्रबुद्ध लोगों के अगुवाई में लड़ा गया। जिसमें 2018 में कुछ सफलता भी मिली। लंबे संघर्ष के बाद बिहार सरकार द्वारा चार लगभग पांच किलोमीटर बंडल 51 करोड़ की लागत से बनाया गया लेकिन विभागीय लापरवाही से बहुत जल्द बंडाल समाप्त भी हो गया। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि एकजूट अहिंसात्मक संघर्ष से सरकार को झुकाने में अवश्य कामयाब होंगे।अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. उमेश प्रसाद सिंह एवं सुभाष चन्द्र जोशी ने आंदोलन पर बैठे महिलाओं एवं पुरुषों में जोश भरते हुए कहा कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। जिस दिन इस क्षेत्र के सशक्त नारी एवं पुरुष की इच्छाशक्ति मजबूत होगी, उसी दिन सरकार को कटाव पीड़ित परिवार के सामने घुटने टेकना होगा और स्थायी समाधान करना होगा। इस आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी पूर्व मुखिया पांडव यादव, वर्तमान मुखिया पांडव महतो, योगेंद्र यादव, राकेश यादव, ओमप्रकाश राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना यादव, विवेका यादव, मिंटू यादव, पप्पू यादव, शंकर यादव रामपुर पंचायत के मुखिया कृष्णानंद यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय पोद्दार, चंद्रशेखर यादव उर्फ़ पप्पू यादव,राजद जिलाध्यक्ष संजय सिंह, साहेब महतो, संजय पोद्दार, देवकीनंदन यादव, उमेश यादव, बबलू यादव, कैलाश यादव, मिंटू यादव, पीयूष यादव, योगेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव, श्रवण कुमार यादव, आकाशदीप यादव, गजेंद्र हिमांशु, पूर्व जिप सदस्य अजीत सरकार, ध्रुव कुमार यादव, रंजीत यादव, सत्तो यादव, पंकज यादव, प्रवीण कुमार, राजीव महतो सहित बड़ी संख्या में सैकड़ो कटाव परिवार की मौजूदगी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर अपनी बातें रखेंगे। मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र के लोगों को इसलिए उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कभी इस क्षेत्र यानी खगड़िया के परवत्ता से विधायक थे।

विपक्ष की नई हुंकार आईएनडीआईए गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में सफल होगा?

आलेख–विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। सत्ता जहां नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश को दिशा देने का प्रयास करती है, वहीं विपक्ष उन नीतियों की समीक्षा कर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का दायित्व निभाता है।इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित आई एन डी आई ए गठबंधन की हालिया बैठक राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने न केवल अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया, बल्कि आने वाले समय के लिए एक साझा राजनीतिक एजेंडा भी तय किया।लोकसभा चुनाव2024 के बाद से आईएनडीआईए गठबंधन कई उतार-चढ़ावों से गुजरा है।कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि चुनाव के बाद गठबंधन की सक्रियता कम हो जाएगी, किंतु हालिया बैठक ने यह संदेश दिया है कि विपक्ष अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की।«बैठक के बाद घोषित पांच बिंदुओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष आने वाले संसद सत्र और राजनीतिक अभियानों में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला है। सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की रही। विपक्ष का आरोप है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं को बढ़ाया है। शिक्षा केवल एक मंत्रालय का विषय नहीं, बल्कि देश के भविष्य का प्रश्न है। जब युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तब यह केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। बैठक में बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है, किंतु रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने की शिकायत लगातार उठती रही है। सरकारी आंकड़े विकास की कहानी कहते हैं तो दूसरी ओर अनेक युवाओं की बेचैनी यह संकेत देती है कि रोजगार सृजन को लेकर अभी भी व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। विपक्ष ने इसी प्रश्न को अपने राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण आधार बनाने का निर्णय लिया है। महंगाई भी उन मुद्दों में शामिल रही जो आम नागरिक के दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। रसोई गैस, खाद्य पदार्थों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विपक्ष का मानना है कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और ठोस समाधान की आवश्यकता है। यही कारण है कि उसने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि इन विषयों पर व्यापक सहमति और समाधान का रास्ता निकाला जा सके। किसानों के प्रश्न भी बैठक के केंद्र में रहे। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और सरकारी योजनाओं के बावजूद किसानों की आय, लागत और बाजार से जुड़े प्रश्न समय-समय पर सामने आते रहे हैं।विपक्ष ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर भी रहा। विपक्षी दलों ने चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के प्रश्नों को उठाने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र में चुनावों की विश्वसनीयता सर्वोच्च महत्व रखती है और यही कारण है कि इस विषय पर राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता स्वाभाविक है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा किआईएनडीआईए गठबंधन अब नियमित अंतराल पर बैठकें करेगा। हर दो महीने में बैठक आयोजित करने और अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि विपक्ष अपनी गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप देना चाहता है। यह केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी गठबंधन की सफलता केवल बैठकों और प्रस्तावों से सुनिश्चित नहीं होती। जनता अंततः परिणामों, विश्वसनीयता और वैकल्पिक दृष्टिकोण को महत्व देती है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहे, बल्कि देश के सामने विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि और आर्थिक प्रगति का एक स्पष्ट वैकल्पिक खाका भी प्रस्तुत करे। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, अवसंरचना विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है और करोड़ों लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ऐसे में आगामी महीनों में सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। नई दिल्ली में हुई आईएनडीआईए गठबंधन की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल विपक्षी दलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्षों की रूपरेखा भी है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रश्नों को केंद्र में रखकर विपक्ष ने अपनी दिशा तय कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह साझा एजेंडा जनता के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त कर पाता है या नहीं। लोकतंत्र में सशक्त सरकार जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक सक्रिय और उत्तरदायी विपक्ष भी है। आईएनडीआईए गठबंधन की यह बैठक इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है,जिसके प्रभाव आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं।

कला संसार में प्रेम, प्रकृति और आत्मा का विलक्षण संगम

लेखक- ललित गर्ग

कला केवल रंगों, रेखाओं और आकृतियों का संयोजन नहीं होती, वह जीवन की अनुभूतियों, संबंधों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। जब दो कलाकार अपने-अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व, दृष्टि और शैली के साथ जीवन की यात्रा में सहयात्री बनते हैं, तब उनकी रचनात्मकता एक नए आयाम को जन्म देती है। डॉ. अनूप कुमार चांद और शुभ्रा चांद की पच्चीस वर्षीय वैवाहिक यात्रा और उनकी समानांतर कला-यात्रा इसी अद्भुत एवं विलक्षण संगम का साक्ष्य है। यह केवल विवाह की रजत जयंती नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और सृजनशीलता के पच्चीस वर्षों का उत्सव है। निश्चित ही कुछ यात्राएँ समय की गणना से नहीं, संवेदनाओं की गहराई से मापी जाती हैं। कुछ संबंध केवल सामाजिक बंधन नहीं होते, वे दो चेतनाओं का ऐसा संगम होते हैं, जहाँ जीवन और सृजन एक-दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। अनूप और शुभ्रा की पच्चीस वर्षीय वैवाहिक यात्रा तथा उनकी कला-साधना ऐसी ही एक दुर्लभ यात्रा है, जिसमें प्रेम केवल भावना नहीं रहा, बल्कि सृजन का मूल बीज बना और कला केवल अभिव्यक्ति नहीं रही, बल्कि आत्मानुभूति का माध्यम बन गई। दिल्ली के इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में तरूण आर्ट गेलैरी के द्वारा 4-7 जून, 2026 तक आयोजित इस संयुक्त प्रदर्शनी में इन कलाकार द्वय की दो शैलियों का आनन्द कलाप्रेमियों ने बढ़-चढ़कर लिया। नई दिल्ली में आयोजित यह 'सृजन के 25 वर्ष' प्रदर्शनी केवल चित्रों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दो रचनात्मक आत्माओं के जीवन-दर्शन का सार्वजनिक उत्सव है। यह प्रदर्शनी बताती है कि कला और जीवन जब एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, तब सृजन का स्वरूप कितना व्यापक और प्रभावशाली हो सकता है। यह आयोजन इस सत्य को पुनः स्थापित करता है कि महान कला केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, पारस्परिक सम्मान और साझा स्वप्नों से जन्म लेती है। आज जब संसार का बड़ा हिस्सा उपभोग, प्रदर्शन और तात्कालिक उपलब्धियों की संस्कृति में उलझा हुआ है, तब अनूप और शुभ्रा की कलायात्रा हमें उस भारतीय कला-दृष्टि की याद दिलाती है, जिसमें कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य का निर्माण नहीं, बल्कि सत्य, शिव और सुंदर की अनुभूति कराना है। भारतीय चिंतन में कला को साधना कहा गया है। साधना का अर्थ है-अपने भीतर उतरना, स्वयं को तराशना और अंततः उस चेतना का स्पर्श करना जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यही तत्व इन दोनों कलाकारों की रचनात्मक सृजन में दिखाई देता है। अनूप की कला प्रकृति से संवाद करती है। उनके चित्रों में समुद्र की लहरें, वन्य जीवन, ग्रामीण जीवन, लोक-संस्कृति और मानवीय संवेदनाएँ केवल दृश्य नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के भीतर धड़कती हुई चेतना की अभिव्यक्ति हैं। वे प्रकृति को वस्तु नहीं मानते, बल्कि एक जीवित सत्ता के रूप में देखते हैं। उनकी कला मानो यह संदेश देती है कि मनुष्य और प्रकृति दो अलग इकाइयाँ नहीं हैं; दोनों एक ही अस्तित्व की परस्पर जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। उनके रंगों में पर्यावरणीय चिंता है, उनकी रेखाओं में करुणा है और उनकी आकृतियों में जीवन के प्रति गहरा सम्मान है। अनूप की कला प्रकृति, लोकजीवन और सामाजिक सरोकारों से संवाद करती है। वे प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के अंतर्मन को पढ़ते हैं, गढ़ते हैं। दूसरी ओर शुभ्रा की कला हमें दृश्य जगत से अदृश्य जगत की ओर ले जाती है। उनके कैनवास पर रंग केवल रंग नहीं रहते, वे ध्यान की मुद्रा बन जाते हैं। वृत्त, सर्पिल और ऊर्जा के विविध रूपों के माध्यम से वे उस ब्रह्मांडीय लय को अभिव्यक्त करती हैं, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में स्पंदित हो रही है। उनकी कला में अध्यात्म किसी धार्मिक प्रतीक या कर्मकाण्ड के रूप में नहीं आता, बल्कि चेतना के विस्तार के रूप में प्रकट होता है। उनके चित्रों को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है मानो रंग ध्यान कर रहे हों और आकृतियाँ मौन में कोई गूढ़ संवाद कर रही हों। उनका कला संसार अमूर्तन, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से निर्मित है। उनके कैनवास पर वृत्त, सर्पिल और रंगों की लय केवल दृश्य संरचनाएँ नहीं, बल्कि चेतना की गहन यात्राएँ हैं। वे दर्शक को बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती हैं। एक कलाकार प्रकृति का कवि है, तो दूसरी आत्मा की चित्रकार। एक धरती की धड़कनों को सुनता है, दूसरी ब्रह्मांड की निस्तब्धता को रंगों में व्यक्त करती है। किंतु आश्चर्य यह है कि दोनों की दिशाएँ अलग होते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही है-मानव संवेदना का विस्तार। वास्तव में अनूप और शुभ्रा की कला भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करती है। अनूप की कला प्रकृति के माध्यम से आत्मा तक पहुँचती है, जबकि शुभ्रा की कला आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड तक। एक बाहर से भीतर की यात्रा है, दूसरी भीतर से बाहर की। किंतु दोनों का गंतव्य एक ही है-चेतना का विस्तार और जीवन की गहनतर समझ। उनके वैवाहिक जीवन के पच्चीस वर्ष भी इसी कला-दर्शन का विस्तार हैं। यह केवल साथ रहने की कहानी नहीं है, बल्कि साथ विकसित होने की कहानी है। सामान्यतः दाम्पत्य में एक व्यक्ति दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, किंतु यहाँ दोनों ने एक-दूसरे की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा। उन्होंने प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को चुना; वर्चस्व नहीं, संवाद को महत्व दिया। यही कारण है कि दोनों की कला स्वतंत्र पहचान रखती है, फिर भी उनके जीवन में अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। अनूप एवं शुभ्रा की वैवाहिक एवं कला यात्रा यह भी सिखाती है कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप स्वामित्व नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व है। जहाँ एक-दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं होती, बल्कि एक-दूसरे के भीतर छिपी संभावनाओं को विकसित होने का अवसर दिया जाता है। यही प्रेम जब कला से जुड़ता है तो वह रचना बन जाता है, और जब जीवन से जुड़ता है तो वह संस्कृति का रूप ले लेता है। हर सफल कलाकृति के पीछे एक गहरी अनुभूति होती है और हर सफल दाम्पत्य के पीछे विश्वास एवं सहयोग का आधार। अनूप और शुभ्रा की कहानी भी इसी सत्य को प्रमाणित करती है। शोध और अध्ययन के दिनों में प्रारम्भ हुई उनकी निकटता केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं थी, बल्कि विचारों, संवेदनाओं और कला-दृष्टि का मिलन भी थी। यह संबंध समय के साथ इतना परिपक्व हुआ कि दोनों ने एक-दूसरे के भीतर छिपे कलाकार को विकसित होने की पूरी स्वतंत्रता और ऊर्जा प्रदान की। उनका दाम्पत्य इस बात का उदाहरण है कि विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि दो आत्माओं की साझा साधना भी हो सकता है। जहाँ सामान्यतः वैवाहिक जीवन में व्यक्तित्वों का संघर्ष दिखाई देता है, वहीं इन दोनों कलाकारों ने व्यक्तित्वों का समन्वय रचा। यही कारण है कि उनका संबंध आज भी उतना ही जीवंत और रचनात्मक दिखाई देता है जितना पच्चीस वर्ष पूर्व था। 'सृजन के 25 वर्ष' केवल एक प्रदर्शनी नहीं है और न ही केवल वैवाहिक रजत जयंती का उत्सव। यह उस विश्वास का उत्सव है कि कला मनुष्य को अधिक मानवीय बना सकती है। यह उस चेतना का उत्सव है जो प्रेम को सृजन में और सृजन को साधना में रूपांतरित कर देती है।

29 साल के ज्वेरेव ने जीता पहला ग्रैंड स्लैम

● फ्रेंच ओपन के फाइनल में कोबोली को हराया, पांच सेट तक चला मुकाबला

पेरिस(एजेंसी)। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराया।

पेरिस में खेले गए मेंस सिंगल्स फाइनल में दूसरी सीड ज्वेरेव ने दसवीं वरीयता प्राप्त फ्लेवियो को पांच सेटों में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से हराया। 29 साल के ज्वेरेव 11 साल से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में खेल रहे हैं। इससे पहले वे ग्रैंड स्लैम में तीन बार फाइनल में और सात बार सेमीफाइनल में हार चुके थे।

फ्रेंच ओपन के अलावा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन को ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कहा जाता है।

टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड जीते थे

ज्वेरेव ने मास्टर्स 1000 इवेंट्स के साथ दो एटीपी फाइल्स भी जीते हैं। टोक्यो में ज्वेरेव ने ओलिंपिक गोल्ड भी जीता था लेकिन उनके खाते में ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं था। इससे पहले 2020 यूएस ओपन, 2024 फ्रेंच ओपन और 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताबी मुकाबला वह हार चुके थे।

6-1 से एक तरफा जीत दर्ज की

ज्वेरेव ने मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए पहला सेट आसानी से 6–1 से जीत लिया। इसके बाद कोबोली ने वापसी की और दूसरा सेट 6–4 से अपने नाम कर लिया। ज्वेरेव ने फिर तीसरा सेट 6–4 से जीता, लेकिन कोबोली ने चौथे सेट को टाई–ब्रेकर में 7–6(5) से जीतकर मुकाबले को पांचवें सेट में पहुंचा दिया। अंतिम सेट में ज्वेरेव ने एक बार फिर 6–1 से एकतरफा जीत दर्ज की।

89 साल बाद कोई जर्मन मेंस खिलाड़ी चैंपियन बना

ज्वेरेव फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले 89 साल के बाद पहले जर्मन मेंस खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले 1937 में जर्मनी के हेनर हेन्केल ने यह टूर्नामेंट जीता था। वहीं, किसी भी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीतने वाले आखिरी जर्मन मेंस खिलाड़ी बोरिस बेकर थे, जिन्होंने 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था।

कौन हैं उपविजेता फ्लेवियो कोबोली

फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल में पहुंचे फ्लेवियो कोबोली इटली के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 24 साल के कोबोली पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कई मजबूत खिलाड़ियों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया।

● मानव-सुंदर के आगे अफगानिस्तान ने घुटने टेके

एक पारी और 300 रनों से भारत जीता

चंडीगढ़ (एजेंसी)। भारत ने महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मुकाबले में अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से रौंदा। पहली पारी में 152 रनों पर सिमटने के बाद अफगानिस्तान को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी इनिंग में मेहमान टीम का हाल और बेहाल रहा और पूरी टीम 112 रन बनाकर सिमट गई। दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान को सेदिकुल्लाह अटल और अब्दुल मलिक ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। अब्दुल 8 रन बनाकर आउट हुए, तो अटल 80 गेंदों में 42 रन बनाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने। गुरबाज दूसरी पारी में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 24 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले रहमत शाह दूसरी इनिंग में 13 रन ही बना सके। कप्तान शाहिदी 5 रन ही बना सके, तो अजमतुल्लाह उमरजई 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

विकेटकीपर-बल्लेबाज अफसर जजई 8 रन बनाकर आउट हुए, तो खरोटी सिर्फ 6 रन ही बना सके। मोहम्मद सलीम बिना खाता खोले आउट हुए और अशरफ चोटिल होने की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं उतरे।

अफगानिस्तान ने 39 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए थे

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत द्वारा बनाए गए 564 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 152 रन बनाकर सिमट गई। मानव सुथार विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुए। टेस्ट के तीसरे दिन अफगानिस्तान ने 113 पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और टीम ने अपने अगले 5 विकेट 39 रन जोड़कर गंवा दिए। अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ रहमत शाह ही भारतीय गेंदबाजों का टिककर सामना कर सके और उन्होंने 60 रनों की पारी खेली। हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। तीसरे दिन की शुरुआत अफगानिस्तान के लिए अच्छी नहीं रही और अजमतुल्लाह उमरजई बिना खाता खोले प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए।

व्यापार

जो भिंडी भारत में 40 रू. किलो, अमेरिका में उसके दाम 7,250

नई दिल्ली, एजेंसी। भिंडी भारतीयों के लिए किसी आम सब्जी जैसी ही है। लेकिन, अमेरिका में इसे इस तरह बेचा जाता है कि कीमत भारत के मुकाबले 18025 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यह बात तब सामने आई जब आशीष आहूजा नाम के एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर अमेरिका के सुपरमार्केट में घूम रहे थे। तभी उन्हें स्नैक वाले सेक्शन में मसालेदार, कुरकुरी तली हुई भिंडी दिखाई दी। 85 ग्राम के छोटे से पैकेट के दाम 6.50 डॉलर यानी लगभग 600 रुपये थे। आहूजा ने हिसाब लगाया तो पता चला कि यह कीमत किलो में करीब 7,250 रुपये बैठती है। इसी भिंडी को आज के दिनों में बड़े आराम से भारतीय बाजारों में 40 रुपये किलो में खरीदा जा सकता है। भारत के आम बाजार और पश्चिमी देशों के ग्रोसरी स्टोर के शेल्फ में जमीन-आसमान का फर्क है। इंस्टाग्राम पर आहूजा ने बताया कि कैसे घर में रोज खाई जाने वाली एक आम सब्जी को अमेरिकी ग्राहकों के लिए पूरी तरह से नए रूप में पेश किया गया है। आशीष आहूजा ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हम भिंडी को रोज खाई जाने वाली आम सब्जी के तौर पर खाते-पीते बड़े हुए हैं। भारत में यह बस एक और सब्जी है। लेकिन, अमेरिका में वे इसे तलते हैं, छोटे पैकेट में पैक करते हैं और अचानक यह शेल्फ पर एक प्रीमियम स्नैक बन जाती है। 85 ग्राम के लिए 6.50 डॉलर।'

आहूजा ने आगे कहा, 'लेज से भी ज्यादा महंगी।' मजाक में कहा, 'यह भिंडी आपसे 'पर्सनैलिटी टैक्स' वसूल रही है। किसी ने भिंडी को नहीं बताया था कि वह ऐसा भी कर सकती है।' वीडियो में आहूजा ने पैकेजिंग और इसकी बहुत ज्यादा कीमत के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, 'तो दोस्तों मैं आपको कुछ बहुत दिलचस्प चीज दिखाता हूं। देखिए, यह क्या है अब, भिंडी जिसका इस्तेमाल हम भारत में सब्जी बनाने के लिए करते हैं। अमेरिका में देखिए, वही चीज स्नैक के तौर पर मिल रही है। मतलब, अच्छी तरह से तली हुई। मसालों और बाकी चीजों के साथ। और इसकी कीमत देखिए। कितनी है यह 6.50 डॉलर है। यानी भारतीय रुपये में यह लगभग 600 रुपये है। और मात्रा कितनी है सिर्फ 85 ग्राम।'

आम चीजों की नए सिरे से पैकेजिंग

इसने इस बात पर भी बहस छेड़ दी कि कैसे दक्षिण एशियाई देशों की आम चीजों को पश्चिम में अक्सर खास वेलनेस या हेल्थ-फूड आइटम के तौर पर नए सिरे से पैक करके बेचा जाता है। जानकारों का कहना है कि कीमतों में इतना बड़ा अंतर साधारण अर्थशास्त्र की वजह से है। सीमित सप्लाई, ज्यादा इंपोर्ट कॉस्ट और भारत के मुकाबले कम डिमांड जहां यह सब्जी सस्ती और आसानी से मिल जाती है।

लोगों को दिखा जबरदस्त बिजनेस आइडिया

जाहिर है, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात पर मजाकिया रिएक्शन दिए। एक यूजर ने मजाक में कहा, 'अमेरिका जाकर तो भिंडी का प्रमोशन ही हो गया।' एक और यूजर ने पीढ़ियों के अंतर वाली मजेदार बात कही– 'भारत में मांओं को बच्चों को यह खिलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं अमेरिका में लोग एक पैकेट के लिए 600 रुपये तक दे रहे हैं।' लोगों ने कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग की ताकत को भी समझा। एक यूजर ने कमेंट किया, 'अच्छी पैकेजिंग और मार्केटिंग का यही कमाल है। सब्जी वही है, लेकिन लोगों की सोच बिल्कुल बदल गई है।' वहीं, एक समझदार यूजर को इसमें बिजनेस का मौका दिखा।

उसने मजाक में कहा, 'किसी को भारत से भिंडी स्नैक्स एक्सपोर्ट करना शुरू करना चाहिए। लगता है कि इसके लिए मार्केट है।'

नौकरी नहीं मिली तो क्या सरकारी लोन से खड़ी कर दी कंपनी

अब 30 लाख सालाना का टर्नओवर

नई दिल्ली, एजेंसी। अमोल भावसार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव के रहने वाले हैं। उन्होंने साबित करके दिखाया है कि बड़े शहरों के बाहर भी कारोबारी सफलता हासिल की जा सकती है। वह ऐसे इलाके से आते हैं जहां सरकारी नौकरी को ही मंजिल माना जाता है। लेकिन, उन्होंने अलग रास्ता चुनकर आने वाले युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। अमोल भावसार ने लगभग 30 लाख रुपये के सालाना टर्नओवर वाला बेवरेज (पेय पदार्थ) का बिजनेस खड़ा कर दिया है। सरकारी नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाए थे। आइए, यहां अमोल भावसार की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

अमोल ने ग्रेजुएशन तो पूरा कर लिया। लेकिन, उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल पाई। जैसे-जैसे वक्त बीता, निराशा बढ़ने लगी। हार मानने के बजाय उन्होंने खुद अपना मौका बनाने का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की थी।

तभी अमोल को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लागू 'पीएम माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम' के बारे में पता चला। उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 25 लाख रुपये का लोन और 7.5 लाख रुपये की सब्सिडी हासिल की।

इस सरकारी स्कीम की मदद से अमोल ने शुरू किया। अपना ब्रांड 'जिंगो सोडा' लॉन्च किया। स्थानीय मांग को समझते हुए उन्होंने तीन फ्लेवर पेश किए- जीरा, बूम और स्पीड। शुरुआत में अमोल ने सिर्फ लोकल मार्केट पर फोकस किया। धीरे-धीरे उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निमाड़ इलाके में फैल गया। आज 'जिंगो सोडा' किराने की दुकानों और छोटे व्यापारियों के पास उपलब्ध है। लोकल ब्रांड होने के कारण इसने जल्द ही स्थानीय ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। अमोल की फैक्ट्री में सोडा बनाने की पूरी प्रक्रिया मशीनों से होती है। बोतल बनाने और लेबल लगाने से लेकर पैकेजिंग तक इसमें सबकुछ शामिल है। इस व्यवस्थित सिस्टम से क्वालिटी एक जैसी बनी रहती है। मार्केट में ब्रांड की विश्वसनीयता मजबूत होती है।

17 परिवारों का सहारा बना यह काम

अमोल का यह काम अब सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं है। यह 17 परिवारों की आजीविका का जरिया भी बन गया है। छोटे शहर में ऐसी यूनिट लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। उनका सालाना टर्नओवर अब लगभग 30 लाख रुपये तक पहुंच गया है। आगे की योजना के तौर पर वह नए फ्लेवर लाने और ब्रांड को जिले से बाहर भी फैलाने की सोच रहे हैं।

युवाओं के लिए मौका

सब्सिडी और ब्याज में छूट मिल सकती है। जिले के किसान और युवा उम्मीदवार मार्गदर्शन के लिए बागवानी और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। अमोल की कहानी साबित करती है कि सही जानकारी, संस्थागत सहयोग और हिम्मत के साथ एक छोटे से शहर से भी शानदार सफलता हासिल की जा सकती है।

बढ़ता ही जा रहा है सीएमआर ग्रीन का जीएमपी

मुंबई, एजेंसी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच एक अच्छा आईपीओ आया तो निवेशक टूट पड़े। तभी तो यह 127 गुना से भी ज्यादा ओवरसब्सक्राइब हो गया। आप तो समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। जिन्होने इसमें अप्लाई किया है वे जानना चाहते हैं कि उन्हें शेयर मिला है या नहीं। आप भी अलॉटमेंट स्टेटस जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं तरीका। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पिछले सप्ताह 3 से 5 जून तक खुला था। इसमें अलॉटमेंट आज यानी सोमवार, 8 जून को तय किए जाने की संभावना है। इसके 10 जून को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है। एक बार जब शेयर अलॉटमेंट का अनुपात तय हो जाएगा तो आप इसे नीचे बनाए गए तरीकों से जांच सकते हैं।

झोली भर कर मिले हैं आवेदन: इस आईपीओ को खूब आवेदन मिले हैं। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक आवेदन करने के अंतिम दिन सीएमआर ग्रीन का आईपीओ 124.04 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 25.03 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था तो नॉन-इंस्टीच्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 172.35 गुना। क्वालिफाइड इंस्टीच्यूशनल बायर्स का हिस्सा तो 270.46 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था।

अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे चेक करें: सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ आवंटन स्थिति ऑनलाइन बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों के माध्यम से चेक की जा सकती है। इसके साथ ही इस पब्लिक इश्यू के रजिस्ट्रार की आधिकारिक साइट पर भी अरप इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। इस आईपीओ का अनलिस्टेड मार्केट या ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। इस समय ग्रे मार्केट में इस कंपनी एक शेयर पर 67.5 का प्रीमियम कोट किया जा रहा है। मतलब कि हर शेयर पर 35.16 फीसदी की कमाई। उल्लेखनीय है कि इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 192 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)